साप्ताहिक

आरएनआई न. :- जेकेएचआईएन/25/ए0631

सबका जम्मू कश्मीर

हिन्दी • वर्ष: 2 • अंक: 12 • कठुआ, शनिवार 21 मार्च 2026 • पृष्ठ: 16 • मूल्य: 5 रूपए

एलजी मनोज सिन्हा ने जम्मू-कश्मीर में शांति और विकास को पटरी से उतारने के प्रयासों के खिलाफ अलगाववादी तत्वों को चेतावनी दी

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने मंगलवार को अलगाववादी तत्वों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में लोगों को बांटने या विकास में बाधा डालने के किसी भी प्रयास से सख्ती से निपटा जाएगा।

सिन्हा ने कहा कि जम्मू और कश्मीर में शांति, कानून व्यवस्था या नागरिकों की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले किसी भी व्यक्ति या समूह को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। तलवारा स्थित सहायक पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में कांस्टेबलों की पासिंग-आउट परेड को संबोधित करते हुए उपराज्यपाल ने कहा, "हमें उन अलगाववादी तत्वों को जड़ से उखाड़ फेंकना होगा जो लोगों को बांटने और विकास को पटरी से उतारने की कोशिश कर रहे हैं। यह उनके लिए एक कड़ी चेतावनी है।" उन्होंने कहा कि शांति भंग करने, व्यावसायिक गति. विधियों को बाधित करने या हिंसा भड़काने के किसी भी प्रयास का कानून के पूर्ण बल से सामना किया जाएगा और जम्मू और कश्मीर पुलिस व्यवस्था और स्थिरता की रक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और ऐसे कृत्यों के खिलाफ बिना किसी अपवाद के सभी आवश्यक उपाय करेगी। कठिन प्रशिक्षण पूरा करने पर जम्मू और कश्मीर पुलिस के "बहादुरों" को बधाई देते हुए उपराज्यपाल ने उनसे केंद्र शासित प्रदेश की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करने का आह्वान किया। "जम्मू और कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद-मुक्त, अपराध-मुक्त केंद्र शासित प्रदेश बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, जहां नागरिक. ों के जीवन पर असुरक्षा का कोई साया नहीं है। सुशासन, नवाचार, सामाजिक एकता और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल करने में बल ने अहम योगदान दिया है।" उपराज्यपाल ने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस की वर्दी पहनने वाला प्रत्येक व्यक्ति उच्च मानकों के साथ जनता की अपेक्षाओं से बढ़कर सेवा देने का संकल्प लेता है। "आज से, जनता का विश्वास आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है – इसे ईमानदारी, निष्पक्षता और सहानुभूति के माध्यम से निरंतर अर्जित करें। आपकी भूमिका कानून लागू करने से कहीं बढ़कर है; इसके सार और आत्मा को आत्मसात करें। मुझे विश्वास है कि आप प्रत्येक नागरिक की गरिमा को बनाए रखेंगे।" उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर पुलिस शांति, सुरक्षा और लो. कतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक नागरिक प्रगति की

■ शेष पेज 2...

राजनाथ सिंह ने ड्रोन निर्माण में आत्मनिर्भरता का आग्रह करने के लिए वैश्विक संघर्षों का हवाला दिया

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत को ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में एक मजबूत और आत्मनिर्भर पारिस्थितिकी तंत्र विक. सित करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने यह बात राष्ट्रीय रक्षा उद्योग सम्मेलन को संबो. धित करते हुए कही। अपने संबोधन में उन्होंने रूस-यूक्रेन तथा ईरान-इजराइल के बीच चल रहे संघर्षों का उल्लेख करते हुए कहा कि इन युद्धों ने आधुनिक युद्ध प्रणाली में ड्रोन और ड्रोन-रोधी तकनीकों की अहम भूमिका को स्पष्ट रूप से उजागर किया है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आज पूरी दुनिया इन संघर्षों

■ शेष पेज 2...

जम्मू-कश्मीर पुलिस की सक्रिय और नवोन्मेषी रणनीति रंग ला रही है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू-कश्मीर पुलिस द्वारा पहाड़ों और जंगलों में आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए तैयार की गई सक्रिय और नवोन्मेषी रणनीति के कारण जम्मू क्षेत्र के ऊपरी इलाकों में आतंकी घटनाओं में उल्लेखनीय कमी आई है।

सूत्रों ने बताया कि 2023-24 में, सीमाव. र्ती जिलों पुंछ और राजौरी, उधमपुर के ऊपरी इलाकों और कठुआ के एक क्षेत्र में आतंकी हमले हुए, जिससे सुरक्षा संबंधी गंभीर चिंताएं पैदा हुईं।

सूत्रों ने कहा, इसी चुनौतीपूर्ण दौर में नलिन प्रभात ने जम्मू-कश्मीर के डीजीपी के रूप में कार्यभार संभाला और दुर्गम इलाकों पर विशेष ध्यान केंद्रित करते हुए आतंकवाद विरोधी अभियानों का पुनर्गठन शुरू किया।

डीजीपी प्रभात ने कार्यभार संभालने के तुरंत बाद ही इस क्षेत्र की अनूठी भौगोलिक चुनौतियों – घने जंगलों, ऊबड़-खाबड़ पहाड़ों और उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों – को पहचान लिया। सूत्रों ने बताया, ष्डीजीपी ने विशेष अभियान समूह (एसओजी) के भीतर एक विशेष परिचालन ढांचा पेश किया। इस रणनीति के तहत, एसओजी के भीतर दो विशिष्ट समूह बनाए गएरू स्नो लेपर्ड्स और मार्खोर। "स्नो लेपर्ड्स यूनिट केंद्रीय रूप से स्थित है और मुख्य रूप से बर्फ से ढके और ऊंचे पर्वतीय शिखरों और

■ शेष पेज 2...

एलपीजी की बुकिंग लगभग सामान्य हो गई है, लेकिन स्थिति अभी भी चिंताजनक बनी हुई है

सबका जम्मू कश्मीर

ई दिल्ली : जी रिफिल की बु. कंग युद्ध-पूर्व सामान्य स्तर के करीब पहुंच रही है, जो धीरे-धीरे सामान्य स्थिति में लौटने का संकेत है। हालांकि, पश्चिम एशिया संघर्ष के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति में जारी बाधाओं के चलते होटलों सहित व्यावसायिक उपभोक्ताओं पर आपूर्ति प्रतिबंध अभी भी लागू हैं, जिससे चिंताएं बनी हुई हैं।

अमेरिका और इजरायल द्वारा 28 फरवरी को ईरान पर किए गए सैन्य हमलों से पहले, 33 करोड़ से अधिक घरेलू एलपीजी उपभोक्ता औसतन प्रतिदिन लगभग 55 लाख सिलेंडर बुक करते थे। इस हमले के बाद तेहरान ने व्यापक जवाबी कार्रवाई की, जिससे होर्मुज जलडमरूमध्य प्रभावी रूप से बंद हो गया। यह एक महत्वपूर्ण समुद्री परिवहन गलियारा है जिसका उपयोग सऊदी अरब, कतर और संयुक्त अरब अमीरात जैसे प्रमुख खाड़ी उत्पादक कच्चे तेल, गैस और एलपीजी को भारत सहित प्रमुख बाजारों में निर्यात करने के लिए करते हैं।

होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से भारत की लगभग 60 प्रतिशत एलपीजी आपूर्ति बाधित हो गई, जिसके चलते वाणिज्यिक उपयोगकर्ताओं को आपूर्ति में कमी आई और घरेलू उपयोगकर्ताओं में अफरा-तफरी मच गई। 13 मार्च को यह संख्या बढ़कर 87.7 लाख तक पहुंच गई।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि 18 मार्च को बुकिंग घटकर 56-57 लाख रह गई है। उन्होंने कहा, अफरा-तफरी में बुकिंग कम

■ शेष पेज 2...

पीएम-मुद्रा के तहत अब तक 39.48 लाख करोड़ रूपये स्वीकृत, एनपीए लगभग 2 प्रतिशत : वित्त मंत्री

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को कहा कि प्रधानमंत्री मुद्रा योजना से कई छोटे उद्यमियों को लाभ हुआ है और इस योजना के शुरू होने के बाद से 39.48 लाख करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 8 अप्रैल, 2015 को शुरू की गई मुद्रा योजना के तहत, कुल ऋणों का लगभग 2 प्रतिशत निष्पादित परिसंपत्तियां (एनपीए) हैं।

राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों के उत्तर देते हुए, सीतारमण ने कहा कि पीएम-मुद्रा सबसे लोकप्रिय योजनाओं

■ शेष पेज 2...

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

शेष पेज 1 से.....

एलजी मनोज सिन्हा...

नई ऊंचाइयों को प्राप्त करे। "सभी संसाधनों और संकल्प के साथ, जम्मू और कश्मीर पुलिस आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता का पालन करती है। हम सभी हितधारक एजेंसियों के साथ एक बहुआयामी रणनीति पर काम कर रहे हैं, और जल्द ही केंद्र शासित प्रदेश आतंकवाद–मुक्त होगा," उन्होंने कहा। कुल 430 प्रशिक्षु कांस्टेबलों ने बुनियादी प्रशिक्षण पूरा करने के बाद दीक्षांत समारोह में उत्तीर्णता प्राप्त की और मंगलवार को आयोजित समारोह में सभी को शपथ दिलाई गई। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को ट्राफियां प्रदान कींरू जॉनी विक्टर (सर्वोत्तम प्रदर्शन), विशाल भरत (द्वितीय सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन), योगेश शर्मा (तृतीय सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम प्रदर्शन), पंकज रैना (इनडोर सर्वश्रेष्ठ), तौसीफ अहमद लोन (आउटडोर सर्वश्रेष्ठ), ताहिर राशिद डार (सर्वश्रेष्ठ निशानेबाज), तस्लीम कोसर (परेड कमांडर) और सुशांत शर्मा (परेड में द्वितीय–कमांड)।

राजनाथ सिंह ने...

पर नजर रखे हुए है और यह साफ दिखाई दे रहा है कि भविष्य के युद्धों में पारंपरिक हथियारों के साथ–साथ ड्रोन तकनीक निर्णायक भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि ऐसे समय में भारत के लिए यह आवश्यक हो जाता है कि वह अपनी रक्षा जरूरतों को पूरा करने के लिए बाहरी देशों पर निर्भर रहने के बजाय स्वयं सक्षम बने। उन्होंने इस दिशा में उद्योग जगत, अनुसंधान संस्थानों और सरकार के बीच बेहतर समन्वय की आवश्यकता पर भी बल दिया।

सिंह ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत को एक ऐसा ड्रोन निर्माण तंत्र विकसित करना चाहिए, जिसमें डिजाइन से लेकर निर्माण तक की पूरी प्रक्रिया देश के भीतर ही संपन्न हो। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता केवल अंतिम उत्पाद तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि इसके हर घटक में भी स्वदेशीकरण जरूरी है। ड्रोन के ढांचे, सॉफ्टवेयर, इंजन और बैटरी जैसे सभी महत्वपूर्ण हिस्सों का निर्माण देश में ही होना चाहिए, तभी सच्चे अर्थों में आत्मनिर्भरता प्राप्त की जा सकती है।

उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह कार्य आसान नहीं है, क्योंकि वर्तमान में दुनिया के अधिकांश देश ड्रोन निर्माण के लिए कई महत्वपूर्ण घटकों का आयात करते हैं। इसके बावजूद उन्होंने विश्वास जताया कि भारत अपनी तकनीकी क्षमता और नवाचार के बल पर इस चुनौती को अवसर में बदल सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से आह्वान किया कि वे अनुसंधान और विकास पर अधिक ध्यान दें तथा गुणवत्ता सुधार को अपनी प्राथमिकता बनाएं।

सम्मेलन में देश की अग्रणी रक्षा निर्माण कंपनियों के शीर्ष अधिक. ारी और रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। इस अवसर पर रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत की रक्षा तैयारियों को मजबूत बनाने और रणनीतिक स्वायत्तता सुनिश्चित करने के लिए यह जरूरी है कि देश रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता से न केवल सुरक्षा मजबूत होगी, बल्कि देश की आर्थिक प्रगति को भी गति मिलेगी।

सिंह ने अपने संबोधन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और स्वचालन जैसी उभरती तकनीकों के महत्व पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि वर्तमान समय में ये तकनीकें वैश्विक स्तर पर विनिर्माण क्षेत्र को पूरी तरह बदल रही हैं। इन नवाचारों के कारण उत्पादन प्रक्रिया अधिक सटीक, तेज और प्रभावी बन रही है। उन्होंने कहा कि भारत को इन तकनीकों को अपनाकर रक्षा उत्पादन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का प्रयास करना चाहिए।

उन्होंने यह भी कहा कि सिमुलेशन तकनीक जैसे नए उपकरण अनुसंधान और परीक्षण की प्रक्रिया को अधिक प्रभावी बना रहे हैं। इससे समय और लागत दोनों की बचत होती है और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार आता है। उन्होंने उद्योग जगत को इन तकनीकों का अधिक से अधिक उपयोग करने के लिए प्रेरित किया।

रक्षा मंत्री ने यह भी रेखांकित किया कि आत्मनिर्भर भारत का लक्ष्य केवल एक नारा नहीं, बल्कि एक व्यापक दृष्टिकोण है, जिसका उद्देश्य देश को हर क्षेत्र में मजबूत बनाना है। उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना राष्ट्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अपने संबोधन के अंत में सिंह ने उद्योग जगत, वैज्ञानिकों और युवाओं से अपील की कि वे देश को तकनीकी रूप से सशक्त बनाने के इस अभियान में सक्रिय भागीदारी निभाएं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि सामूहिक प्रयासों और दृढ़ संकल्प के साथ भारत आने वाले समय में ड्रोन निर्माण के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत पहचान बना सकेगा।

जम्मू–कश्मीर पुलिस...

चोटियों पर अभियान चलाने के लिए तैनात है।

केंद्र शासित प्रदेश में फैली मार्खोर यूनिटें विशेष रूप से प्रशिक्षित हैं और उन्हें वन क्षेत्रों और पहाड़ी इलाकों पर प्रभुत्व स्थापित करने के लिए तैनात किया गया है, ये वे क्षेत्र हैं जिनका इस्तेमाल आतंकवादी समूह लंबे समय से घुसपैठ और छिपने के लिए करते रहे हैं।"

"परिचालन क्षमता बढ़ाने के लिए, इन यूनिटों के चयनित कर्मियों को आंध्र प्रदेश के ग्रेहाउंड्स भेजा गया और उन्हें विशिष्ट सेना यूनिटों के साथ जंगल युद्ध, सहनशक्ति और विशेष युद्ध तकनीकों में उन्नत प्रशिक्षण दिया गया।

इस क्षमता निर्माण पहल ने उच्च क्षेत्रों के प्रतिकूल और चुनौतीपूर्ण वातावरण में काम करने की बल की क्षमता को काफी मजबूत किया।"

इस रणनीतिक बदलाव के परिणाम स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहे हैं।

उन्होंने कहा, "2025 तक, क्षेत्र में आतंकी घटनाओं की संख्या में उल्लेखनीय कमी आई, जो बेहतर खुफिया समन्वय, बेहतर क्षेत्र प्रभुत्व और खतरों के त्वरित शमन को दर्शाती है।"

"इस रणनीति ने न केवल आतंकी नेटवर्क को बाधित किया बल्कि विभिन्न जिलों के दूरदराज के क्षेत्रों में स्थानीय आबादी के बीच सुरक्षा की भावना को भी बहाल किया।"

गौरतलब है कि डीजीपी प्रभात ने हाल ही में एसटीसी तलवारा में आयोजित पासिंग आउट परेड को संबोधित करते हुए कहा कि जम्मू–कश्मीर पुलिस ने आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी रणनीति में बदलाव किया है। उन्होंने कहा, "पिछले दो वर्षों में जम्मू–कश्मीर पुलिस ने अपनी परिचालन रणनीति में बदलाव किया है और दूरदराज के जंगलों और पहाड़ों में कार्रवाई तेज कर दी है, जहां आतंकवादियों ने फिर से संगठित होने का प्रयास किया है। अब लड़ाई जंगलों और पहाड़ी इलाकों में पहुंच गई है। हम इन क्षेत्रों में ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं ताकि आतंकवादियों को पकड़ सकें और उनके ठिकानों को नष्ट कर सकें।"

उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस अब जंगलों में आतंकवादियों से सक्रिय रूप से मुकाबला कर रही है। उन्होंने कहा, "हमारे अभियान हमारे कुटिल पड़ोसी द्वारा भेजे गए आतंकवादियों का मुकाबला करने के उद्देश्य से चलाए जा रहे हैं। हम उन्हें उनकी नापाक योजनाओं में सफल नहीं होने देंगे।"

पिछले साल के "ऑपरेशन महादेव" को याद करते हुए डीजीपी ने कहा कि सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन के दौरान तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को मार गिराया था। "ये आतंकवादी बैसरन (पहलगाम) क्षेत्र में 26 नागरिकों की हत्या के लिए जिम्मेदार थे। पुलिस ने जंगल में काफी अंदर तक उनका पीछा किया और अंत में उन्हें मार गिराया।"

एलपीजी की बुकिंग...

हो रही है,ष और साथ ही यह भी बताया कि सरकार घरेलू उपयोग के लिए उपलब्ध एलपीजी की आपूर्ति को प्राथमिकता दे रही है।

हालांकि, उन्होंने कहा, "एलपीजी (आपूर्ति) की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, लेकिन किसी भी एलपीजी वितरक के पास आपूर्ति की कमी नहीं है।"

व्यावसायिक उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता का केवल पांचवां हिस्सा ही मिल रहा है।

शर्मा ने बताया कि पिछले दो हफ्तों में घरेलू एलपीजी उत्पादन में 40 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि हुई है और तीनों सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां युद्ध–पूर्व स्तर पर एलपीजी रिफिल की दैनिक आपूर्ति कर रही हैं।

"हमारी आपूर्ति में कोई कमी नहीं आई है। कुछ दिनों तो आपूर्ति (युद्ध–पूर्व काल से भी अधिक) रही है। 18 मार्च को 56 लाख से अधिक एलपीजी सिलेंडरों की बुकिंग के मुकाबले 54.91 लाख सिलेंडर वितरित किए गए," उन्होंने कहा।

तेल कंपनियां बुकिंग के अनुरूप एलपीजी की आपूर्ति बनाए रखने के लिए अतिरिक्त शिफ्ट में काम कर रही हैं। उन्होंने 13 मार्च को 62. 5 लाख सिलेंडर और 14 मार्च को 60 लाख सिलेंडर वितरित किए दृ ये दोनों दिन बुकिंग के चरम पर थे।

उन्होंने बताया कि मौजूदा भू–राजनीतिक तनाव के बीच एलपीजी आपूर्ति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, वितरक केंद्रों पर किसी भी तरह की कमी की सूचना नहीं मिली है और घरेलू सिलेंडर वितरण निर्बाध रूप से जारी है।

ऑनलाइन बुकिंग में भारी वृद्धि हुई है और यह 94 प्रतिशत तक पहुंच गई है, जबकि डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड (एलपीजी सही ग्राहकों तक पहुंच रही है यह सुनिश्चित करने के लिए पंजीकृत मोबा. इल नंबरों पर भेजा जाने वाला एक विशिष्ट ओटीपी) का कवरेज 83 प्रतिशत तक बढ़ गया है।

इसके अलावा, शहर के गैस नेटवर्क के पास रहने वाले ग्राहकों को पाइप वाली प्राकृतिक गैस (एलपीजी) पर स्विच करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है – जो एलपीजी का एक सुविधाजनक विकल्प है क्योंकि ईंधन बिना रिफिल बुकिंग की झंझट के लगातार पाइपों के माध्यम से घरों की रसोई तक पहुंचता है।

उन्होंने कहा, षपिछले दो हफ्तों में 1.25 लाख नए घरेलू, वाणिज्यिक और औद्योगिक कनेक्शन जारी किए गए हैं।ष

कालाबाजारी रोकने के लिए छापेमारी और निरीक्षण जारी हैं, कई राज्यों में सिलेंडर जब्त किए जा रहे हैं और एफआईआर दर्ज की जा रही हैं।

केंद्र सरकार ने 18 मार्च को सभी राज्य सरकारों को पत्र लिखकर कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाने और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा था।

उन्होंने आगे कहा कि केरोसिन जैसे वैकल्पिक ईंधनों को बढ़ावा दिया जा रहा है और वाणिज्यिक एलपीजी भंडार राज्यों को उनकी प्राथमिकता सूची के अनुसार उपयोग करने के लिए उपलब्ध कराए गए हैं।

पीएम–मुद्रा के तहत...

में से एक है और इससे कई छोटे उद्यमियों को लाभ हुआ है।

ष्योजना के शुरू होने के बाद से 39.48 लाख करोड़ रुपये स्वीकृ त किए जा चुके हैं। इसलिए यह सबसे बड़ी बैंक ऋण योजनाओं में से एक है, जो उन लोगों तक पहुंची है जिनके पास गिरवी रखने के लिए कुछ भी नहीं है,ष सीतारमण ने कहा, और आगे बताया कि पीएम–मुद्रा के तीन घटक हैं, शिशु, किशोर और तरुण।

31 मार्च, 2025 तक, शिशु योजना में कुल ऋण राशि के मुकाबले 12.4 प्रतिशत बकाया है। किशोर में कुल दी गई राशि का 9.48 प्रतिशत बकाया है, जबकि तरुण में 7.92 प्रतिशत बकाया है।

उन्होंने बताया कि बैंक इन बकाया ऋणों की वसूली के लिए प्रयासरत हैं।

सीतारमण ने कहा, "श्रेणीवार देखें तो, शिशु में यह अपेक्षाकृत कम है। इस श्रेणी के तहत कुल वितरित राशि का केवल 1.83 प्रतिशत ही एनपीए है।"

शिशु ऋण उन लोगों को दिए जाते हैं जो अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए छोटी राशि उधार लेते हैं।

मंत्री ने कहा, "वैसे तो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कुल एनपीए लगभग 2 प्रतिशत या उसके आसपास, यानी 2.3 प्रतिशत ही है। ऐसा नहीं है कि बहुत अधिक एनपीए हैं और यह व्यापक रूप से फैला हुआ है, इसलिए हमें कोई बड़ी कार्रवाई करनी होगी। इनमें से अधिकांश लोग बैंकों के आसपास ही रहते हैं, इसलिए वे लगभग हर दिन बैंक के संपर्क में रहते हैं, और अब हम इसमें सुधार कर रहे हैं।"

एक लिखित उत्तर में, सीतारमण ने बताया कि पिछले तीन वर्षों (अप्रैल 2022 से मार्च 2025) के दौरान प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत 15.50 लाख करोड़ रुपये के 18.37 करोड़ से अधिक ऋण स्वीकृत किए गए हैं, जिनमें से लगभग 19 प्रतिशत ऋण नए उद्यमियों/खातों को और 65 प्रतिशत ऋण महिला उद्यमियों को दिए गए हैं।

पीएमएमवाई के तहत एनपीए की वसूली के लिए बैंकों द्वारा उठाए गए कदमों में निरंतर फॉलो–अप, ग्राहकों से संपर्क की आवृत्ति में वृद्धि, किश्तों का पुनर्निर्धारण और एकमुश्त निपटान (ओटीएस) शामिल हैं।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर विदेश मंत्रालय ने चिंता जताई

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली, 19 मार्च : पश्चिम एशिया में संघर्ष के वैश्विक परिणामों के साथ विस्तार के बीच, भारत ने गुरुवार को कहा कि यह स्थिति न केवल देश के लिए, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक ष्चुनौतीपूर्ण समयष है।

पश्चिम एशिया की स्थिति पर यहां आयोजित एक अंतर–मंत्रालयी ब्रीफिंग में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने यह भी कहा, ष्हम अपनी ऊर्जा सुरक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के लिए संबंधित देशों के साथ लगातार संपर्क में हैं।ष क्षेत्र में जारी संघर्ष गुरुवार को 20वें दिन में प्रवेश कर गया। पश्चिम एशिया संघर्ष 28 फरवरी को शुरू हुआ जब अमे. रिका–इजराइल गठबंधन ने ईरान पर सैन्य हमले किए। जवाबी कार्रवाई में, तेहरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों वाले खाड़ी देशों को निशाना बनाया है। जायसवाल ने कहा, ष्हां, यह न केवल हमारे लिए, बल्कि पूरे वैश्विक समुदाय के लिए एक चुनौतीपूर्ण समय रहा है। हमारे नेता अपने समकक्षों के संपर्क में हैं, जैसा कि मैंने अभी हमारे प्रधानमंत्री और कुवैत के क्राउन प्रिंस के बीच हुई बातचीत का जिक्र किया। इसी तरह, हम कई अन्य नेताओं के साथ भी संपर्क में हैं। उनसे पूछा गया कि क्या पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष ने चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिदृश्यों में नई दिल्ली के कूटनीतिक दृष्टिकोण की परीक्षा ली है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर
कठुआ, शनिवार, मार्च 21, 2026 | 3

पढ़ने की लौ एवं किताबों से नाता अटूट है

पुस्तकें चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन हैं। उत्तम विचारों से युक्त पुस्तकों के प्रचार-प्रसार से युवाओं को नई दिशा दी जा सकती है। देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जा सकता है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार हैं, उन्हें पढ़कर व्यक्ति के भीतर कुछ महान करने की आकांक्षा जागती है।

ललित गर्ग

53वें भारत मंडपम् में 10 से 18 जनवरी 2026 तक नौ दिनों के किताबों के जमावडे ने एक बात स्पष्ट कर दी है कि किताबों से नाता कभी नहीं टूट पायेगा। इस मेले में 35 से अधिक देशों के एक हजार से अधिक प्रकाशक भाग ले रहे हैं। यह भव्य विश्व पुस्तक मेला केवल पुस्तकों की खरीद–फरोख्त का आयोजन नहीं है, बल्कि यह उस जीवंत पुस्तक–संस्कृति का उत्सव है, जिसे अनेक लोग डिजिटल युग में कमजोर मानने लगे थे। एक–एक किलोमीटर लंबी कतारें, बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की उत्सुक भागीदारी और पुस्तकों के प्रति बढ़ता आकर्षण इस धारणा को स्वस्थ करता है कि पुस्तकें जीवन का अभिन्न हिस्सा रही हैं और भविष्य में भी रहेंगी। इंटरनेट, सोशल मीडिया एवं अन्य इलेक्ट्रोनिक माध्यमों पर अपार पाठ्य सामग्री एवं साहित्य उपलब्ध होने के बावजूद पुस्तक मेलों में इतनी भीड़ क्यों आ रही है? छपी हुई पुस्तकें एवं शब्द केवल ज्ञान, जिज्ञासा और मनोरंजन की विशाल दुनिया के दरवाजे नहीं खोलते, वे हमें गंध, स्पर्श, संवेदना, सोच, अनुभूति की प्रेरक, अनुकरणीय एवं रोमांचक दुनिया में भी ले जाते हैं। इस वर्ष के पुस्तक मेले के दृश्य पुस्तक–संस्कृति के प्रति नई आशा, नया विश्वास और नया उत्साह पैदा करते हैं। यह मेला स्पष्ट संकेत देता है कि पढ़ने की प्रवृत्ति केवल जीवित ही नहीं है, बल्कि नए पंखों के साथ उड़ान भर रही है।

पुस्तक मेला वस्तुतः एक विश्व उत्सव है–ऐसा उत्सव जो ज्ञान, विचार, कल्पना और संवाद को एक साझा मंच देता है। दुनिया भर में पुस्तकों के दायरे को पहचानने, उन्हें प्रोत्साहित करने और संस्कृतियों को जोड़ने के लिए यह आयोजन अतीत और भविष्य के बीच एक मजबूत कड़ी तथा पीढ़ियों और सभ्यताओं के बीच एक सेतु का कार्य करता है। यही कारण है कि यूनेस्को हर वर्ष पुस्तक उद्योग के तीन प्रमुख क्षेत्रों–प्रकाशक, पुस्तक विक्रेता और पुस्तकालयों के अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ मिलकर विश्व पुस्तक राजधानी का चयन करता है, ताकि पुस्तक–संस्कृति की प्रेरणा पूरे वर्ष बनी रहे। यह पहल इस बात का प्रमाण है कि पुस्तकें केवल ज्ञान का माध्यम नहीं, बल्कि वैश्विक संवाद और मानवीय एकता का भी आधार हैं। किताबें अपने सभी रूपों में–मुद्रित, ई–बुक, ऑडियो हमें सीखने, सोचने और स्वयं को सशक्त बनाने का अवसर देती हैं। वे हमारा मनोरंजन करती हैं, हमें दुनिया को समझने में मदद करती हैं और दूसरों की दुनिया में झांकने का अवसर देती हैं। इस साल का मेला 'भारतीय सैन्य इतिहासरू वीरता और ज्ञान/75' थीम पर आधारित है, जो भारत की रक्षा बलों के महत्वपूर्ण पलों, योगदानों और कहानियों पर ध्यान केंद्रित करता है। 'थीम मंडप 2026' दर्शकों के लिए विशेष आकर्षण बना हुआ है। यह मंडप भारत की सैन्य विरासत के 75 वर्षों की ऐतिहासिक और निर्णायक यात्रा को दिखा रहा है, जिसकी जड़ें शौर्य, प्रज्ञा और नैतिक मूल्यों में निहित हैं. इसमें कथाओं, दृश्यात्मक प्रस्तुतियों और संवाद के माध्यम से 1947 से लेकर ऑपरेशन सिंदूर 2025 तक भारत की सैन्य यात्रा को रेखांकित करता है। दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला वैश्विक साहित्यिक परिदृश्य में एक प्रतीकात्मक उत्सव बन चुका है। इस मेले में विश्वप्रसिद्ध लेखकों का आगमन होता है, साहित्यिक संवाद, विमर्श और चर्चाएं होती हैं। विलियम शेक्सपियर, मिगुएल डे सर्वेंट्स जैसे विश्व साहित्य के स्तंभों से लेकर भारतीय भाषाओं के महान साहित्यकारों तक की रचनाएं यहाँ पाठकों को एक साथ उपलब्ध होती हैं। यह मेला भारतीय साहित्य को वैश्विक मंच देता है और साथ ही विश्व साहित्य को भारतीय पाठकों से जोड़ता है। पुस्तकों को 'ज्ञान का बाग' कहा गया है। जो व्यक्ति पुस्तकों से सच्ची दोस्ती कर लेता है, उसे जीवन भर ज्ञान का संबल मिलता है। कठिन समय में पुस्तकें मित्र की तरह साथ देती हैं, मार्गदर्शन करती हैं और समाधान की दिशा दिखाती हैं। पुस्तक का महत्व सार्वभौमिक, सार्वकालिक और सार्वदेशिक है। किसी भी युग में, किसी भी तकनीकी आंधी में उसका महत्व कम नहीं हो सकता। इंटरनेट, सोशल मीडिया और कृत्रिम बुद्धिमत्ता जैसी अनेक क्रांतियां आई हैं और आगे भी आएंगी, लेकिन पुस्तक–संस्कृति अपनी उपयोगिता और प्रासंगिकता बनाए रखेगी। कारण स्पष्ट है–पुस्तकें केवल सूचना नहीं देतीं, वे चिंतन, मनन और विवेक का विकास करती हैं। तकनीक ने ज्ञान के क्षेत्र में क्रांति अवश्य की है, लेकिन यह हर समय संभव नहीं कि किताबों के स्थान पर केवल स्क्रीन से पढ़ा जाए। पुस्तक का स्पर्श, उसकी सुगंध, पन्नों को पलटने का अनुभव और पढ़ते हुए होने वाला एकांत संवाद–ये सभी तत्व पुस्तक को विशिष्ट बनाते हैं। पुस्तकें मानसिक रूप से मजबूत बनाती हैं, सोचने–समझने का दायरा बढ़ाती हैं और व्यक्ति को आत्मअनुशासन सिखाती हैं। पुस्तकें जाग्रत देवता के समान हैं। उनका अध्ययन, मनन और चिंतन तत्काल लाभ देता है। महात्मा गांधी के जीवन पर गीता, टॉल्स्टॉय और थोरो के विचारों का गहरा प्रभाव था। इसी तरह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वैचारिक निर्माण और वैश्विक छवि के निर्माण में पुस्तकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वे स्वयं एक सजग पाठक रहे हैं और पुस्तक–संस्कृति को जीवंत करने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने 'मन की बात' जैसे अभिनव कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ने, लिखने और विचार करने की संस्कृति को जन–जन तक पहुँचाया है। उनका संदेश 'बुकें दे, बुके नहीं' केवल एक प्रतीकात्मक नारा नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक दृष्टि है–जहाँ उपहार में फूलों के गुलदस्ते की बजाय ज्ञान का उपहार देने की प्रेरणा दी गई है। वे मानते हैं कि सत्साहित्य की शक्ति तोप, टैंक और परमाणु अस्त्रों से भी अधिक है, क्योंकि हथियार ध्वंस करते हैं, जबकि साहित्य मानव–मूल्यों में आस्था पैदा करता है और स्थायी परिवर्तन लाता है। सत्साहित्य समाज में सकारात्मक परिवर्तन का आधार बनता है–ऐसा परिवर्तन जो सत्ता और कानून से किए गए परिवर्तनों से कहीं अधिक टिकाऊ होता है। इसी कारण प्रधानमंत्री मोदी भारत के परिवर्तन में पुस्तक–संस्कृति और सत्साहित्य की निर्णायक भूमिका को स्वीकारते हैं। उनके नेतृत्व में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारतीय भाषाओं को बढ़ावा, स्थानीय साहित्य का सम्मान और पठन–संस्कृति को प्रोत्साहन देने की दिशा में ठोस पहलें देखने को मिलती हैं।

पुस्तकें चरित्र निर्माण का सर्वोत्तम साधन हैं। उत्तम विचारों से युक्त पुस्तकों के प्रचार–प्रसार से युवाओं को नई दिशा दी जा सकती है। देश की एकता और अखंडता का पाठ पढ़ाया जा सकता है और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण किया जा सकता है। पुस्तकें प्रेरणा का भंडार हैं, उन्हें पढ़कर व्यक्ति के भीतर कुछ महान करने की आकांक्षा जागती है। वे कल्पवृक्ष भी हैं और कामधेनु भी, क्योंकि उनकी छाया में मनुष्य अपनी आंतरिक क्षमताओं को पहचानता है। आज का इंसान घर बदलता है, पहनावा बदलता है, रिश्ते और मित्र बदलता है, फिर भी असंतुष्ट रहता है क्योंकि उसने पुस्तकरूपी कल्पवृक्ष की छाया छोड़ दी है। पुस्तकें व्यक्ति को बदलने का मार्ग दिखाती हैं–सोच, व्यवहार और दृष्टि को सकारात्मक दिशा देती हैं। जब तक व्यक्ति स्वयं को नहीं बदलता, वह अपनी मंज़िल नहीं पा सकता। आत्मानुशासन, आत्मचिंतन और आत्मविकास–ये सभी पुस्तक–संस्कृति की देन हैं। इंटरनेट और ई–पुस्तकों की बढ़ती पहुँच के बावजूद छपी हुई किताबों का महत्व कम नहीं हुआ है। वे आज भी प्रासंगिक हैं और रहेंगी। हजारीप्रसाद द्विवेदी का कथन–"साहित्य वह जादू की छड़ी है, जो पशुओं में, ईंट–पत्थरों में और पेड़–पौधों में भी विश्व की आत्मा का दर्शन करा देती है", आज भी उतना ही सार्थक है। निश्चित ही, विश्व पुस्तक मेला की प्रेरणा भारतीय जन–चेतना को झकझोर रही है और उन्हें नए भारत–सशक्त भारत के निर्माण की दिशा में प्रेरित कर रही है। साररूप में यह कहा जा सकता है कि दिल्ली का विश्व पुस्तक मेला पुस्तक–संस्कृति और पढ़ने की प्रवृत्ति को नए पंख देने वाला एक अत्यंत उपयोगी और प्रासंगिक आयोजन है। इसका उद्घाटन करते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अपने संबोधन में कहा कि पुस्तकें ज्ञान का वाहक हैं जो पीढ़ियों को जोड़ती हैं, सभ्यताओं की स्मृतियों को संजोती हैं और समाज को दिशा देती हैं। यह मेला केवल पुस्तकों का नहीं, विचारों का, संस्कारों का और भविष्य का मेला है–जहाँ शब्द समाज का निर्माण करते हैं और पन्ने इतिहास की दिशा तय करते हैं।

– ललित गर्ग

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

दिल्ली में 10 से 18 जनवरी 2026 तक आयोजित विश्व पुस्तक मेले ने एक बार फिर यह सिद्ध कर दिया कि डिजिटल युग के बढ़ते प्रभाव के बावजूद पुस्तकों का महत्व कम नहीं हुआ है। इस मेले में 35 से अधिक देशों के हजारों प्रकाशकों ने भाग लिया, जिससे यह एक वैश्विक सांस्कृतिक और बौद्धिक मंच बन गया। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक की उत्साही भागीदारी ने यह दर्शाया कि पढ़ने की संस्कृति आज भी जीवंत है। यह मेला केवल पुस्तकों की खरीद-बिक्री तक सीमित नहीं, बल्कि ज्ञान, विचार, संवाद और कल्पना का उत्सव है। "भारतीय सैन्य इतिहासरू वीरता और ज्ञान/75" थीम ने विशेष आकर्षण पैदा किया, जिसमें देश की सैन्य परंपरा और गौरवशाली इतिहास को प्रदर्शित किया गया। इंटरनेट और सोशल मीडिया के दौर में भी पुस्तकों का स्पर्श, उनकी गहराई और आत्मीय अनुभव अद्वितीय है। पुस्तकें न केवल ज्ञान प्रदान करती हैं, बल्कि सोचने-समझने की क्षमता, नैतिक मूल्यों और आत्मविकास को भी प्रोत्साहित करती हैं। यह मेला समाज में पढ़ने की आदत को मजबूत कर राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देता है।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

संघ और अमरीका : जिन पे तकिया था, वही पत्ते हवा देने लगे!!

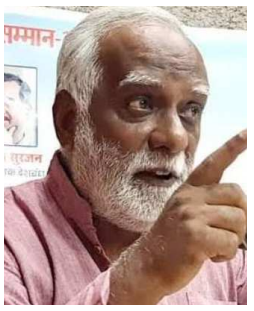

बादल सरोज

न तो इन्होने शेक्सपीयर को पढने का झंझट पाला हैं, न इन्हें क्लियोपेट्रा के बारे में ही कुछ मालूम है, वरना ताजे अमरीकी कारनामे पर जुलियस सीजर के अंदाज में हैरत जताते हुए आहत भाव से इतना तो कहते ही कि 'हे ब्रूटस तुम भी'!! क्योंकि हाल के दौर में न जाने क्या–क्या सहने, करने और गगनचुम्बी चाटुकारिता की पातालगामी मिसालें कायम करने के बाद भी कमबख्त अमरीका ने सीधे मर्म पर चोट की है।

ट्रम्प की रहनुमाई वाली संघीय सरकार के धार्मिक स्वतन्त्रता पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग — यूएस कमीशन ओन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम दृ ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानि आरएसएस को लोगा. ं की धार्मिक स्वतन्त्रता के हनन और हिंसक कार्यवाहियों का जिम्मेदार मानते हुए इस पर प्रतिबन्ध लगाने, इससे जुड़े व्यक्तियों के अमरीका प्रवेश पर रोक लगाने तथा उनकी संपत्तियों को जब्त करने सहित 6 सिफारिशें की हैं। इसी मार्च में जारी इस रिपोर्ट में इस अमरीकी आयोग ने कई घटनाओं के उल्लेख के साथ भारत को चिंताजनक देशों की सूची में शामिल किया है और संयुक्त राज्य अमरीका की सरकार से कहा है कि वह भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों तथा व्यापार के रिश्तों को तय करते समय इन बातों को आधार बनाए। आयोग ने हथियारों की आपूर्ति रोकने की तक की बात कही है। इस रिपोर्ट में आरएसएस के साथ खुफिया एजेंसी रॉ का भी नाम है दृ जिसके पीछे कनाडा में लगे आरोप हो सकते हैं।

ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पिछले कुछ वर्षों से इस तरह के उल्लेख होते रहे हैं। इसी तरह की एक रिपोर्ट के आधार मौजूदा प्रधानमंत्री जब गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तब उनको 'अवांछित व्यक्ति' घोषित कर उनके अमरीका प्रवेश पर प्रतिबन्ध लगाया जा चुका है। इस तरह की रिपोर्ट्स को ऐन्वेई मानकर अनदेखा नहीं किया जा सकता, बाद में इन्ही को बहाने के रूप में इस्तेमाल किये जाने के ढेर उदाहरण मौजूद हैं।

वैसे अमरीका न तो दुनिया का दरोगा है, न सरपंच कि बाकी देशों को सर्टिफिकेट बांटता फिरे, मगर संघ और भाजपा के मामले में ऐसा इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत में दृ शायद दुनिया में भी दृ ये अकेला ऐसा कुनबा है, जो अपने पड़ोसी देशों के बारे में अमरीकी आयोगों और एजेंसियों के इस तरह के एलानों को ईश्वरीय वचन मानकर फुदकते रहता है। इसलिए भी कि हाल के दौर में तो इन्होने अपने आपको अमरीका के साथ कुछ इस कदर नत्थी कर लिया है कि कई बार तो खुद अमरीकी भी संशय में पड़ जाते हैं कि वे अपने देश के प्रति ज्यादा वफादार हैं या कोई साढ़े तेरह हजार किलोमीटर दूर धरती के दूसरे कोने पर बैठे संघी और भाजपाई उनसे भी ज्यादा हैं।

2014 में सत्ता में आने के बाद साफ़–साफ़ नजर आने वाला एक यही काम तो हुआ है। कभी भरे गले से बराक ओबामा को अपना जिगरी बताया और उससे तू–तड़ाक के संबंधों का बखान खुद गा–गाकर सबको सुनाया। ट्रम्प के साथ तो रही सही दूरियां भी इस कदर नजदीकियां बन गयीं कि इधर हाउडी ट्रम्प, हिंदी में बोले तो 'कैसा है रे ट्रम्पवा', तो उधर हाउडी मोदी के तमाशे होने लगे। लगाव इतना उन्मुक्त हुआ कि सारी कूटनीतिक भद्रता की भद्रा उतारते हुए 'अब की बार ट्रम्प सरकार' का नारा बनकर अगले के चुनाव प्रचार तक जा पहुंचा। हालांकि अगले को इससे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ दृ उस चुनाव में उसकी लुटिया डूब ही गयी। चार साल बाईडेन को रिझाते मनाते गुजरे, मगर ट्रम्प के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद तो जैसे सारे तटबंध ही टूट गए।

उसके बाद जो–जो और जैसा–जैसा हुआ है और उससे भारत जैसे देश की जितनी भद्द पिटी है, उसकी इतिहास में कोई दूसरी मिसाल नहीं है। ओबामा को बराक बराक उवाचने वाले प्रधानमंत्री मोदी ने ट्रम्प को तुरंतई 'माय डिअर फ्रेंड डोलांड' कहकर ऊंची आसंदी पर विराज दिया और उसका जो सिला उनके दोस्त ने दिया, उसे देखकर 'हुए तुम दोस्त जिनके दुश्मन उसका आसमाँ क्यों हो' मिसरा याद आ गया।

श्माय डिअर फ्रेंड' ने पहला झटका तो शपथ ग्रहण समारोह में न बुलाकर दिया। उसके बाद बड़ी मानमनुहार और जुगाड़ करने के बाद जब मुलाक़ात के लिए पहुंचे, तो प्रेस कांफ्रेंस में लाइव कैमरों के सामने ही हड़काकर तत्काल नीतियाँ बदलने का हुकुम सुना दिया। मगर मजाल है कि इस पर मुंह से कोई बोल तक फूटा हो!मुलाक़ात करके वापस लौट आने के बाद भी किसी तरह की अप्रसन्नता या असहमति नहीं जताई गयी। मोदी संघ के प्रचारक, भाजपा के नेता या निजी हैसियत से नहीं गए थे। वे अमरीका के राष्ट्रपति के सामने 140 करोड़ नागरिकों के प्रधानमंत्री के नाते बैठे थे, जबकि ऐसे ही बर्ताब पर अमरीकी रहमोकरम पर जिंदा यूक्रेन के ज़ेलिंसकी तक ने ट्रम्प को खरी खरी सुना दी थीं, मगर जैसा कि खुद ट्रम्प ने बार बार कहा है, मोदी उन्हें खुश करने के जरिये ढूंढ रहे थे, सो नाराज कैसे करते। इसके बाद तो दुनिया के इस सबसे घिनौने राष्ट्रपति ने जैसे भारत को पंचिंग बैग ही बना लिया और अपमानों की अंतहीन झड़ी ही लगा दी और वह आज भी जारी है।

पहलगाम के बाद बजाय भारत का साथ देने के धमकी देकर युद्ध रुकवाने के दावे को तो उसने जैसे तकिया कलाम ही बना लिया। गिनने वाले बताते हैं कि बन्दा अब तक कोई एक सौ बार कह चुका है कि उसने फोन करके धमकाया और युद्ध रुक गया।

असली संख्या इससे अधिक ही होगी। इतना ही नहीं, अपनी इस 'उपलब्धि' की बिना पर भाई ने खुद को नोबल देने की मांग भी खुद ही कर डाली। मजाल है जो हस्तिनापुर में बैठे मोदी या उनके किसी अदने अफसर ने मिमियाकर भी इसका खंडन किया हो। जले पर नमक छिडकने के लिए इसी माय डिअर फ्रेंड ने पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को दाव. तें देना शुरू कर दी रू उसके सेनाध्यक्ष को अपने एक प्रमुख राष्ट्रीय दिन के समारोह का मेहमाने खुस. ूसी बनाया, एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था का सर्वेसर्वा बना दिया। इस तरह एक बार फिर जान–बूझकर अंगूठा भी दिखाया, मुंह भी चिढ़ाया। मगर इधर से 'छोड़ेंगे सब मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे' का दोस्ती राग बजता रहा।

उसके बाद टैरिफ ब्लैकमैलिंग आयी, सरकार ब्लैकमेल हुई। व्यापार समझौता हुआ। बाद में ट्रम्प ने उसका एलान पहले ही कर दिया, जबकि पड़ोसी बांग्लादेश उससे कहीं बेहतर डील लेने में कामयाब हुआ।

रूस से तेल न खरीदने सहित और कितनी शर्तें किस तरह मानी हैं, यह अब सब जानते हैं।

एक समय जो भारत दुनिया के 118 गुटनिरपेक्ष देशों का सर्वमान्य नेता था, उसे इतना ज्यादा अमरीका अनुमति आश्रित बना दिया कि वह अपने हजारों वर्ष पुराने दोस्त देश के सर्वोच्च नेता की हत्या पर शोक भी नहीं जता पाया।

इतना ज्यादा झुकने के बाद भी अच्छा अभिनेता होने के कटाक्ष के सिवा कुछ नहीं मिला। यह मजाक उड़ाने वाली टिप्पणी सिर्फ जुबान फिसल जाने का मामला नहीं था रू पहले ट्रम्प की सहयोगी और वित्त सलाहकार स्कॉट बेसेंट का कहना और उसके बाद अमरीकी राष्ट्रपति भवन की प्रवक्ता और प्रेस सेक्रेटरी कैरोलिन लेविट द्वारा इसका दोहराया जाना साबित करता है कि यह एक सम्प्रभु देश को निशाना बनाकर, उसके योजनाबद्ध मानमर्दन के सिलसिले का हिस्सा है।

ये कुछ उदाहरण इसलिए गिनाये गए हैं, ताकि समझा जा सके कि इधर से झुकने में कोई कसर न छोड़ने के बाद भी उधर से हैसियत दिखाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जबकि उधर वाले जानते हैं कि ये बंदे जन्म–जन्म से वफादारी निबाहते रहे हैं। जब अमरीका नहीं था, तब इनके लिए अंग्रेज थे दृ भाई लोगों के लिए वे भी इतने ही दिल फरेब थे। अंग्रेज चले गए, मगर आदत नहीं छूटी। ट्रम्प की दोनों जीतों के लिए यज्ञ किये, हवन किये, पाठ किये, अनुष्ठान किये। ट्रम्प तो ट्रम्प, उसके जुड़वां बेंजामिन नेतन्याहू तक के लिए यही सब बार–बार किये। इतना सब कुछ करने के बाद भी 'हे ब्रूटस तुम भी' का दोहराया जाना बहुत बेइंसाफी है।

वह भी तब, जब आका के देश में अपनी अच्छे बच्चे की छवि बनाने और उनसे मेल–मुलाकात बढ़ाने के लिए आरएसएस ने 3 लाख 30 हजार डॉलर दृ आज की कीमत के हिसाब से कोई 3 करोड़ रूपये खर्च किये। अमेरिकी लॉबिंग फर्म स्क्वायर पैटन बोग्स (एसपीबी) और एक अन्य लॉबिंग फर्म, स्टेट स्ट्रीट स्ट्रैटेजीज (एसएसएस), जो वन+ स्ट्रैटेजीज के नाम से कारोबार करती है, को तीन किश्तों में फीस देकर काम पर लगाया। हासिल क्या हुआ? प्रतिबन्ध की सिफारिश और सम्पत्ति जब्त करने की सलाह!!

और जैसी कि इन दिनों चुप्प रहने की परम्परा बन गयी है, इस बार भी उसी का निर्वाह किया।

धार्मिक स्वतन्त्रता पर अंतर्राष्ट्रीय आयोग की इस रिपोर्ट पर दृ इन पंक्तियों के लिखे जाने तक दृ न तो प्रधानमंत्री बोले, न किसी मंत्री ने मुंह खोला। और तो और, समालखा में अपनी सौंवी सालगिरह का जश्न मना रहे आरएसएस ने भी नहीं बोला है। एक अदने से अधिकारी भर ने बयान दिया है, वह भी इतना लिजलिजा है कि न लीपने का है न पोतने का। तू कौन, मैं खामखाँ कहकर अमेरिका को उसकी सीमा में रहने की हिदायत देने के बजाय अधिकारी ने अमेरिका में मंदिरों पर होने वाले हमला. ं, भारतीय समुदाय के लोगों पर हिंसा का हवाला दिया है। प्रतिक्रिया का यह तरीका एक तरह से अमरीकी आयोग के कहे को स्वीकार कर लेने जैसा है कि हम करते हैं तो क्या हुआ, आपके देश में भी तो ऐसा होता है। इस अधिकारी के जवाब में सिर्फ मंदिरों भर का उल्लेख भी तोहमत का कबूलनामा ही है।

असली दुविधा उन भा भा भाओं दृ भारत से भागे भारतवासियों दृ की है, जो मोदी की सभाओं में अबकी बार ट्रम्प सरकार के जैकारे लगा–लगाकर गला बिठाए हुए थे, जो दुनिया भर में आरएसएस की शाखाएं खोले हुए हैं और भर भर झोली डॉलर और पोंड्स, येन और मार्क इकट्ठा करके नागपुर भेजते रहते हैं। संघ की इस वैश्विक भुजा के संयोजक इसी अमरीका में रहने वाले सौमित्र गोखले हैं, ये श्रीमान भी अभी तक कुछ नहीं बोले हैं। इस सहित दुनिया भर में और जितनी भी शाखाएं हैं, उनके संयोजकों सहित सब के सब आरएसएस के प्रचारक हैं। हालांकि अमरीका में छवि बनाने और अमरीका के बड़े अधिकारियों तथा मंत्रियों आदि से भेंट मुलाक़ात करवाने के लिए तीन करोड़ रूपये दिए जाने के खुलासे के बाद संघ के आरएसएस के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील अंबेकर द्वारा यह सफाई दी गयी थी कि आरएसएस "केवल भारत में" काम करता है। उनका यह दावा रंगे हाथों पकड़े जाने पर मुकर जाने की संघ की स्थायी अदा के सिवा कुछ नहीं था। अम्बेकर की इस सफाई के कुल जमा छः सप्ताह बाद ही हैदराबाद में संघ की वैश्विक भुजा, जिसे आरएसएस के प्रचारक संघ का विश्व विभाग बताते हैं, का शिविर हुआ, जिसमें दुनिया भर के 79 देशों के 1,600 लोग शामिल हुए। स्वयं सरसंघचालक मोहन भागवत इसमें हिस्सा लेने पहुंचे थे।

यह कोई नया संगठन या उपक्रम नहीं है। साल 2006 में संघ के मुखपत्र ऑर्गनाइजर में छपी एक खबर के अनुसार, तब हर पांच साल में यह शिविर हुआ करता था, अब हर वर्ष होने लगा है, और उस वर्ष के शिविर के मुख्य अतिथि 2002 के नरसंहार से ख्याति पाए गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी थे। इससे पहले 1995 की प्रेस विज्ञप्ति ने बताया था कि वैश्विक संघ हिन्दू स्वयंसेवक संघ, सेवा इंटरनेशनल, विश्व हिन्दू परिषद्, हिन्दू स्टूडेंट्स कौंसिल और फ्रेंड्स ऑफ़ इंडिया सोसाइटी इंटरनेशनल आदि–आदि संगठन आरएसएस के अनुषंगी संगठन हैं। मतलब यह कि इनकी सांगठनिक मौजूदगी है, जो बाकी जो हो सो हो, भारत के किसी काम की नहीं है। दुनिया के अलग–अलग देशों में बैठे इतने सारे संगठन भारत के लिए कुछ करते हैं या कभी रीगन, तो कभी ट्रम्प के लिए ही मंच सजाते रहते हैं? यह जानना दिलचस्प होगा कि हाल में ट्रम्प द्वारा लगभग भारत विरोधी मुहिम छेड़े जाने के वक्त संघ की अमरीकी शाखा ने क्या किया? कोई बयान तक देने का भी साहस जुटाया या नहीं। इन सब पर बोलने की उम्मीद करना तो दूर की बात है, अभी मार्च में जारी इस रिपोर्ट और उसमें की गयी सिफारिशों पर भी कुछ कहने की हिम्मत नहीं हो पायी है।

मतदान की तारीखों का ऐलान : पर क्या चुनाव होगा भी!

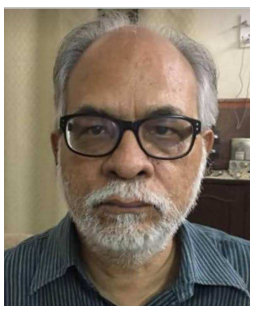

राजेंद्र शर्मा

वर्तमान मामले में तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव पर पर्याप्त संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर जमा होने के बाद, इसके किसी सदन में विचार के लिए स्वीकार किए जाने समेत, अनेकानेक चरणों से क्रमवार आगे बढ़ना बाकी है। इसलिए, इस प्रस्ताव का हश्र क्या होगा इस पर अटकल लगाने का कोई उपयोग नहीं है। वैसे भी जब वर्तमान चुनाव आयोग पर असली आरोप सत्ताधारी भाजपा के साथ पक्षपात करने का है।

चुनाव आयोग ने 15 मार्च को विधानसभाई चुनावों के अगले चरण की तारीखों की घोषणा कर दी। कहने की जरूरत नहीं है कि चुनाव आयोग ने इन तारीखों की घोषणा करने के लिए, चुनाव में जाने वाले राज्यों के प्रधानमंत्री मोदी के चुनाव से ऐन पहले के दौरे के पूरे हो जाने का इंतजार किया। इस दौरे में प्रधानमंत्री ने हरेक राज्य में एक ओर परियोजनाओं के उद्घाटनों से लेकर घोषणाओं तक का सरकारी काम–काज किया और दूसरी ओर, अपनी पार्टी के पक्ष में राजनीतिक–चुनावी प्रचार किया। अपने चुनाव–पूर्व चुनाव प्रचार के दौरों के इस चक्र में प्रधानमंत्री मोदी ने 11 मार्च को केरल का दौरा किया। 12 मार्च को प्रधानमंत्री तमिलनाडु के दौरे पर रहे। 13 मार्च को असम में प्रधानमंत्री का घोषणा–प्रचार दौरा हुआ और 14 मार्च को प्रधानमंत्री प. बंगाल के दौरे पर पहुंचे, जहां मुश्किल से आधे भरे ब्रिगेड मैदान में रैली के साथ, उन्होंने अपने दौरे का समापन किया। और अगले ही दिन चुनाव आयोग ने विधानसभाई चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी।

बेशक, यह कोई पहली बार नहीं हुआ है, जब चुनाव की तारीखों की घोषणा और प्रधानमंत्री के चुनाव–पूर्व प्रचार कार्यक्रम की तारीखों में ऐसा सटीक तालमेल हुआ हो। उल्टे, 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी राज की स्थापना के बाद से जितने भी महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं, उन सभी में यह सचेत तालमेल देखने को मिला है। वास्तव में अब तो यह इस हद तक सामान्य बनाया जा चुका है कि शुरू में कुछ चुनावों के मामले में इस पर सवाल उठाए जाने के बाद, धीरे–धीरे न सिर्फ मीडिया तथा टीकाकारों ने, बल्कि विरोधी राजनीतिक पार्टियों तक ने इस पर सवाल उठाना तक बंद कर दिया है। हैरानी की बात नहीं है कि इस बार भी, सोशल मीडिया पर छुटपुट टिप्पणियों को छोड़कर, चुनाव आयोग की इस कारगुजारी को शायद ही किसी ने ध्यान देने लायक समझा हो।

लेकिन, ऐसा होने से चुनाव आयोग के इस खेल में निहित बेईमानी, किसी तरह से छोटी या महत्वहीन नहीं हो जाती है। उल्टे यह तो इसी का इशारा करता है कि किस तरह, चुनाव आयोग से एक संवैधानिक निकाय के रूप में स्वतंत्र तथा निष्पक्ष तरीके से काम करने की अपेक्षाएं, अब समाप्तप्रायरू हैं। इसे देखते हुए हैरानी की बात नहीं है कि स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार, वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त, ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग के खिलाफ, लगभग समूचा विपक्ष औपचारिक रूप से अपना श्अविश्वासश जताने के लिए तैयार हो गया है और उसे हटाने के लिए संसद के सामने विधिवत रूप से प्रस्ताव लाया गया है।

सवाल यह नहीं है कि विपक्ष के चुनाव आयोग के खिलाफ इस तरह के कदम के सफल होने की कोई संभावनाएं हैं भी हैं या नहीं? भारत के संविधान निर्माताओं ने, जनतंत्र के लिए स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव की और स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए, हर प्रकार के दबावों से सुरक्षित चुनाव आयोग सुनिश्चित करने की मंशा से, मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों को हटाए जाने की प्रक्रिया को, पर्याप्त से अधिक कठिन बनाया है। हालांकि, संसद के हाथों में यह अधिकार सौंपा गया है, लेकिन संसद भी कोई साधारण बहुमत से चुनाव आयुक्तों को नहीं हटा सकती है। इसकी प्रक्रिया वैसी ही जटिल तथा अद्र्ध–न्यायिक है, जैसी उच्चतर न्यायालय के न्यायाधीशों के मामले में इंपीचमेंट की प्रक्रिया होती है।

वर्तमान मामले में तो मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव पर पर्याप्त संख्या में सांसदों के हस्ताक्षर जमा होने के बाद, इसके किसी सदन में विचार के लिए स्वीकार किए जाने समेत, अनेकानेक चरणों से क्रमवार आगे बढ़ना बाकी है। इसलिए, इस प्रस्ताव का हश्र क्या होगा, इस पर अटकल लगाने का कोई उपयोग नहीं है। वैसे भी जब वर्तमान चुनाव आयोग पर असली आरोप सत्ताधारी भाजपा के साथ पक्षपात करने का है, संसद के दोनों सदनों में सत्तापक्ष की संख्या को देखते हुए, किसी चमत्कार से ही इस प्रस्ताव को कामयाबी मिल सकती है, अन्यथा इसका विफल होना तो तय ही है। इसके बावजूद, जिसमें इस प्रस्ताव का विफल होना तयशुदा होना भी शामिल है, इस प्रस्ताव का रखा जाना निरर्थक नहीं है। इस प्रस्ताव का रखा जाना, मौजूदा हालात पर आलोचना की एक नैतिक आवाज है, जहां सत्ताधारी भाजपा और उसकी मोदीशाही ने, जनतंत्र को चलाने वाली सभी संस्थाओं को इस तरह भीतर से खोखला कर दिया है कि, उनकी साख ही खत्म हो गयी है। वर्तमान की विद्रूपताआ.ं की ऐसी नैतिक आलोचना पेश करना ही, विपक्ष का असली काम है। वैसे तो जनमत निर्माता के रूप में मीडिया का भी यही काम है, लेकिन मोदीशाही ने एक संस्था के रूप में मीडिया को पहले ही इस कदर खोखला कर दिया है कि वह वर्तमान की आलोचना करना भूल ही गया है और सिर्फ सत्ताधारियों की खुशामद करने के लायक रह गया है।

प्रसंगवश कहते चलें कि ऐसी ही नैतिक आलोचना प्रस्तुत करने का काम, संसद के चालू सत्र में लोकसभा स्पीकर, ओम बिड़ला के खिलाफ आए अविश्वास प्रस्ताव ने किया था, जो कि स्वतंत्र भारत के इतिहास का इस तरह का तीसरा ही प्रस्ताव था। बेशक, वह अविश्वास प्रस्ताव विफल हो गया और ओम बिड़ला लोकसभा स्पीकर के पद पर बने हुए हैं।

याद रहे कि इससे पहले, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ भी सदन में उनके पक्षपातपूर्ण आचरण के लिए, अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। लेकिन, उस प्रस्ताव को सदन में विचार के लिए स्वीकार ही नहीं किया गया, हालांकि इसके कुछ ही समय बाद धनखड़ ने अचानक राज्यसभा के सभापति तथा उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके कारणों को लेकर अब तक रहस्य बना ही हुआ है। अगर अविश्वास की इस तरह की अभिव्यक्तियां, वर्तमान व्यवस्था की जनतांत्रिक आला.ं चना का बहुत ही जरूरी हिस्सा हैं, तो बार–बार इस तरह अविश्वास जताए जाने की नौबत आना, बेशक वर्तमान जनतांत्रिक व्यवस्था के संकट की गहराई को दिखाता है। और अविश्वास की ऐसी अभिव्यक्तियों को भी अनसुना कर के मौजूदा व्यवस्था का उसी रास्ते पर चलते रहना, मिसाल के तौर पर ओम बिड़ला का या मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश गुप्ता का, अपने ओहदे का पहले जितना ही पक्षपातपूर्ण तरीके से उपयोग करते रहना, वर्तमान शासन द्वारा रचे गए इस संकट के वर्तमान शासन के रहते असाध्य होने को ही दिखाता है।

खैर! विधानसभाई चुनावों के आगामी चक्र पर लौटें, जिसकी तारीखों की 15 मार्च को चुनाव आयोग ने घोषणा की है। इन तारीखों को तय करने में भी चुनाव आयोग की अतार्किक मनमानी की ओर अनेक टिप्पणीकारों ने ध्यान खींचा है। मिसाल के तौर पर असम, केरल तथा पुडुचेरी के चुनाव, एक ही चरण में 9 अप्रैल को हो जाएंगे। इसके पूरे 14 दिन बाद, 23 अप्रैल को तमिलनाडु के चुनाव होंगे और प. बंगाल के पहले चरण के चुनाव होंगे। प. बंगाल के दूसरे चरण के चुनाव 29 अप्रैल को होंगे और इसके पांच दिन बाद, 4 मई को वोटों की गिनती की जाएगी।

इसका नतीजा यह है कि असम, केरल तथा पुडुचेरी को मतदान के बाद, नतीजों के लिए पूरे 25 दिन इंतजार करना पड़ेगा। ऐसा क्यों? अनेक टिप्पणीकारों ने इस पर भी सवाल उठाए हैं कि आखिरी चरण के मतदान और मतगणना के बीच पांच दिन का अंतर क्यों? जब ईवीएम से पहले के जमाने में, मतदान के एक–डेढ़ दिन में ही मतगणना शुरू हो जाती थी, तो ईवीएम मशीनों के जमाने में मतदान और मतगणना में इतना लंबा अंतराल क्यों जरूरी है? यह भी याद दिला दें कि विशेष रूप से 2024 के आम चुनाव के बाद से, चुनाव आयोग ने मतदान की शाम के बाद, मतगणना के दिन तक मत फीसद का आंकड़ा बढ़ाने को जैसे नियम ही बना लिया है, जिसका कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण अब तक नहीं दिया गया है। इसी प्रकार कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण, कुल डाले गए वोटों और गिने गए वोटों की संख्या बेमेल होने की, अधिकांश चुनाव क्षेत्रों में सामने आने वाली समस्या का भी नहीं दिया गया है। चुनाव आयोग के आम पक्षपातीपन के साथ जुड़कर यह सब, चुनाव की पूरी प्रक्रिया को ही गहरे संदेहों के घेरे में ले आता है।

और अंत में एक बात और। खासतौर पर प. बंगाल और असम में प्रधानमंत्री के 13–14 मार्च के दौरे और उसके पहले गृहमंत्री अमित शाह के दौरों से साफ हो गया है कि भाजपा, कम से इन दोना.ं राज्यों में यह चुनाव सबसे बढ़कर तथाकथित बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर लड़ने जा रही है, जो मुस्लिमविरोधी प्रचार और लामबंदी का ही दूसरा नाम है। प्रधानमंत्री ने श्रोटी, माटी, बेटी पर खतरेश का नारा भी दे दिया है। 2024 के आम चुनाव के समय से ही खुद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भाजपा, इस खुल्लमखुल्ला सांप्रदायिक मंच का लगातार सहारा ले रही है। बिहार के विधानसभा चुनाव में मुस्लिम बहुल सीमांचल क्षेत्र में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के लिए खासतौर पर इसका सहारा लिया गया था। लेकिन, जो चुनाव आयोग आम चुनाव के बाद से सत्ताधारी पार्टी को इस सांप्रदायिक दुहाई का बेरोक–टोक इस्तेमाल करने दे रहा है, क्या अचानक अपनी कुंभकर्णी नींद से जागेगा और सत्ताधारी पार्टी की इस बढ़ती प्रवृत्ति को रोकेगा? याद रहे कि चुनाव में सांप्रदायिक दुहाई का सहारा लेना, एक चुनावी अपराध है।

यह भी याद रहे कि प. बंगाल में चुनाव आयोग की एसआईआर की मनमानी ने, जिसे केंद्र की सत्ताधारी पार्टी का ही आशीर्वाद हासिल नहीं है, (जिसका घुसपैठिया राग ही इस मनमानी के केंद्र में है), जिसे सुप्रीम कोर्ट का भी अनुमोदन हासिल है, पचास लाख से ज्यादा मतदाताओं के मताधिकार पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर दिए हैं। श्न्यायाधीनश के नाम पर संदेह की सूची में डाले गए ये पचास लाख से ज्यादा नाम, 2024 के आम चुनाव की मतदाता सूचियों में पचास लाख से ज्यादा नाम काटे जाने के ऊपर से हैं।

मतदाता सूचियों की ऐसी चीर–फाड़ के बाद, क्या जनता की इच्छा की अभिव्यक्ति के रूप में, चुनाव को कोई अर्थ भी रह जाएगा?

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार और साप्ताहिक पत्रिका श्लोकलहरश के संपादक हैं।)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

नागरिक परिक्रमा

संजय पराते

1. छत्तीसगढ़ का अल्पसंख्यक विरोधी धर्मांतरण–विरोधी कानून

छत्तीसगढ़ में भाजपा सरकार ने कांग्रेस के बहिर्गमन के बाद विधानसभा से धर्मांतरण विरोधी कानून पारित करा लिया है और अब यह राज्यपाल की मंजूरी के लिए उनके ऑफिस में है। भाजपा सरकार के अनुसार यह कानून प्रदेश में बड़े पैमाने पर हो रहे जबरन और अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के उद्देश्य से पारित किया गया है। मकसद सिर्फ इतना ही होता, तो वर्तमान कानूनों में ही इसकी पर्याप्त व्यवस्था है। लेकिन हाथी के दांत दिखाने और खाने के अलग–अलग होते हैं। असली बात यह है कि संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता के जो मूल्य निहित हैं, उसको निष्प्रभावी करना, अल्पसंख्यकों के अधिकारों का दमन करना और समाज में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को तेज करना। यह इससे भी साबित होता है कि इस विधेयक को पारित करते हुए जय श्रीराम का नारा लगाना भाजपाई नहीं भूले। ष्राम–रामष् के सौम्य अभिवादन को कट्टर सांप्रदायिक, असहिष्णु और आक्रामक छवि वाले अल्पसंख्यक विरोधी ष्जय श्रीरामष् में बदलने का श्रेय तो आखिर संघी गिरोह को ही जाता है। इसलिए, यदि सदन में भाजपा विधायक इस विधेयक को कानून बनाते हुए यह नारा लगाते हैं, तो उसके निहितार्थ और संदेश बहुत ही स्पष्ट हैं।

छत्तीसगढ़ में भाजपा राज में अल्पसंख्यकों और उनके अधिकारों पर बहुत तेजी से हमले बढ़े हैं। खासकर ईसाई समुदाय के खिलाफ, धर्मांतरण के छद्म मुद्दे को केंद्र में रखकर ये हमले किए जा रहे हैं। हर दिन छत्तीसगढ़ के किसी–न–किसी हिस्से में धर्मांतरण किए जाने के शक और अपुष्ट आरोपों पर, संघी गिरोह द्वारा ईसाई समुदाय की प्रार्थनाओं पर हमले किए जाने और उत्पात मचाने की खबरें आ रही हैं। इन हुड़दंगियों को सरकार और प्रशासन का पूरा संरक्षण मिल रहा है। महज शक और झूठे आरोपों में उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी प्रार्थना को रोका जा रहा है, जबकि हमारा संविधान सभी धर्मों के लोगों को अपनी आस्था और विश्वास के अनुसार पूजा–पाठ, प्रार्थना और नमाज की स्वतंत्रता देता है। इसी प्रकार, मुस्लिम लड़के और हिंदू लड़की के प्रेम–प्रसंगों को लव जिहाद का नाम दिया जा रहा है और मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, जबकि संविधान दो वयस्क लोगों को प्रेम करने और विवाह करने की छूट देता है।

अपने सार रूप में यह कानून वास्तव में महिलाओं और युवाओं के खिलाफ है, क्योंकि यह एक वयस्क व्यक्ति को अपनी पसंद से जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता पर हमला करता है। आज जब 18 वर्ष में युवाओं को मताधिकार दिया जा रहा है, यह मानना कि युवाओं में अपने जीवन साथी के बारे में सही फैसला लेने की समझ नहीं होती, पूरी तरह से पोंगापंथी सोच ही है, जिसे संघी गिरोह इस देश पर लादना चाहता है। यह कानून इस देश के नागरिकों की स्वतंत्रता और निजता के अधिकार का सीधा–सीधा उल्लंघन है, क्योंकि दो अलग–अलग धर्मों के व्यक्तियों के बीच विवाह को बाधित करने और रोकने की कोशिश करता है।

यह हास्यास्पद है कि जिस कानून को कथित "लव जिहाद" की आड़ में लाया जा रहा है, जिसके बारे में पिछले कुछ वर्षों से केवल भ्रामक प्रचार चल रहा है, उसके बारे सरकार के पास कोई ठोस तथ्य नहीं है। संसद में ही मोदी सरकार में अमित शाह के नेतृत्व वाले गृह मंत्रालय ने माना है कि लव जिहाद नाम की कोई चीज नहीं है और न ही इसे पुष्ट करने के लिए कोई आंकड़े है। इसका अर्थ यही है कि मुस्लिम और अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के खिलाफ संघी गिरोह का यह नफरती प्रचार है।

छत्तीसगढ़ के इस कानून में अन्य भाजपा शासित राज्यों की तरह ही धर्मांतरण करने और अंतर्धार्मिक विवाह के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिसकी प्रमुख बात यह है कि इन कामों के लिए सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेनी होगी। धर्म किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत मामला और विश्वास है। इसी प्रकार, किसी व्यक्ति को किससे विवाह करना है, यह संबंधित व्यक्तियों की निजी पसंद का सवाल है और शुद्ध रूप से निजी मामला है। इसमें राज्य के हस्तक्षेप की अनुमति कैसे दी जा सकती है? यदि इस मामले में किसी कानून का उल्लंघन होता है या अपराध होता है, तो इससे निपटने के लिए भी वर्तमान कानूनों में पर्याप्त व्यवस्था है।

इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती मिलने की पूरी संभावना है। अन्य भाजपा शासित राज्यों में पारित इसी तरह के कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल ही रही है। ऐसे में छत्तीसगढ़ सरकार को ऐसा कोई कानून बनाने से पहले सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का इंतजार करना चाहिए था, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार में धैर्य नहीं है, क्योंकि इस कानून का वास्तविक उद्देश्य तो सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करना और अल्पसंख्यकों को प्रताड़ित करना है।

'2. ऐसे सुप्रीम कोर्ट की क्षय हो!'

मासिक धर्म पर महिलाओं को अवकाश दिए जाने की एक जनहित याचिका को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जायमाल्या बागची की पीठ ने कहा है कि इससे महिलाओं के रोजगार की संभावनाओं पर प्रतिकूल असर पड़ेगा, क्योंकि ऐसी बाध्यताओं के चलते मालिक व नियोक्ता रोजगार में महिलाओं को नियुक्त करने से वंचित कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की यह अवधारणा संविधान में निहित एक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के विरुद्ध है, शोषण की प्रक्रिया और रूढ़िवादी विचारों को मजबूत करने वाली है और इसलिए सरासर महिला विरोधी टिप्पणी है।

गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट की यह पहली बार की गई महिला विरोधी टिप्पणी नहीं है। इससे पहले इसी पीठ द्वारा घरेलू कामगार महिलाओं को न्यूनतम मजदूरी देने के लिए कानून बनाने के लिए दायर की गई याचिका को भी खारिज करते हुए टिप्पणी की थी कि घरेलू कामगारों के लिए न्यूनतम पारिश्रमिक का कानून बनाने का मतलब होगा कि ऐसे लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा।

संविधान का अनुच्छेद–14 और अनुच्छेद–21 हमारे देश के नागरिकों को समानता और गरिमा पूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। इस अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह केंद्र और राज्य सरकारों को ऐसे नीतिगत विषयों पर नीति या कानून बनाने का आदेश दे सकती है। लेकिन उक्त दोनों याचिकाओं की खारिजी से ऐसा लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस अधिकार को त्याग दिया है। इसके पहले खाद्यान्न सुरक्षा, मध्यान्ह भोजन सहित न जाने कितने विषय हैं, जिन पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकारों को नीति बनाने का आदेश दिया था।

महिलाओं के हित में दाखिल जनहित याचिकाओं को खारिज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जिन तर्कों का सहारा लिया है, वे अत्यंत ही आपत्तिजनक है। यदि इन तर्कों का सहारा लिया जाता, तो अतीत में इस दुनिया से न तो गुलामी की व्यवस्था का खात्मा होता और न ही बंधुआ गुलामी खत्म होती, न तो मजदूरों को 8 घंटे के काम का अधिकार मिलता और न ही न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार। ये सभी अधिकार इस दुनिया और हमारे देश के लोगों को एक समतापूर्ण और शोषणविहीन समाज के निर्माण के संघर्ष के क्रम में ही मिले हैं और एक सभ्य समाज की ओर बढ़ने के लिए यह संघर्ष आज भी जारी है। इन संघर्षों ने मेहनतकशों को जिस अनुपात में गुलामी और शोषण की बेड़ियों से मुक्त किया है, उसी अनुपात में शोषक वर्ग के सकल मुनाफों पर भी चोट की है।

समानता के अधिकार को तब तक सुनिश्चित नहीं किया जा सकता, जब तक कि हमारे समाज के विशेष रूप से कमजोर तबकों और लोगों की विशेष आवश्यकताओं को पूरा नहीं किया जाता। इसीलिए संविधान विकलांगों की विशेष देखभाल करने का निर्देश सरकारों को देता है। ठीक इसी प्रकार, जो लोग घरों में काम करते हैं, आठ घंटे काम करने के बाद उनको जीवन निर्वाह योग्य न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो, इसकी निगरानी संविधान की रक्षक सुप्रीम कोर्ट और सरकारें नहीं करेंगी, तो और कौन करेगा? क्या इन घरेलू मजदूरों के शोषण और उनको बदतर स्थिति में ही जीवन यापन करने की इजाजत इस आधार पर दी जा सकती है कि इससे इन घरों के मालिकों पर आर्थिक चोट पहुंचेगी?

मासिक धर्म के मामले में भी यही बात है। प्राकृतिक रूप से महिलाओं की शारीरिक संरचना पुरुषों से भिन्न होती है, विशेषकर प्रसव के मामले में। इसलिए महिलाओं की शारीरिक संरचना को ध्यान में रखते हुए यदि उनकी शिक्षा और रोजगार के संबंध में विशेष प्रावधान नहीं किए जाएंगे, तो महिलाओं और पुरुषों के बीच समानता की बात केवल जुबानी और कागजों तक ही सीमित रह जाएगी। इसलिए महिलाओं को मुफ्त पैड देने और मासिक धर्म के दिनों में उन्हें विशेष अवकाश देने की माग पर एक बड़ा आंदोलन खड़ा होता दिख रहा है, ताकि वे इन दिनों थकान, बुखार, उल्टी, भंयकर दर्द, अत्यधिक रक्तस्राव जैसी स्वास्थ्य समस्याओं में आराम कर सकें।

जापान, इंडोनेशिया, जांबिया, स्पेन, दक्षिण कोरिया और चीन सहित दुनिया के बहुत से देशों में मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं के लिए अवकाश की व्यवस्था पहले से ही मौजूद है। दुनिया मातृत्व अवकाश से आगे बढ़कर पितृत्व अवकाश की ओर भी बढ़ रही है। भारत में भी बिहार और कर्नाटक में मासिक धर्म के दिनों में अवकाश दिया जा रहा है। कुछ निजी कंपनियां जैसे जोमैटो, स्विगी, एकर इंडिया, एलएनटी, ओरिएंट इलेक्ट्रिक आदि भी मासिक धर्म पर अवकाश की सुविधा प्रदान कर रही है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट का यह मानना कि इस सुविधा की मांग पर करने पर नियोक्ता महिलाओं को रोजगार नहीं देंगे, असंगत और तथ्यों से परे है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं के जीवन से जुड़े एक बहुत बड़े अधिकार के मामले में हस्तक्षेप करने से इंकार कर दिया है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर मासिक धर्म अवकाश के लिए कानून का बनना आज की सबसे बड़ी जरूरत है, क्योंकि यह कदम पुरुषों और महिलाओं के बीच लैंगिक भेदभाव दूर करने और समानता की ओर बढ़ने वाला कदम है।

मोदी राज में जिस तरह बड़ी तेजी के साथ संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का क्षरण हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट भी उससे अछूता नहीं है। दरअसल, हमारे देश में संघी गिरोह जिस सांप्रदायिक–कॉर्पोरेट राज को आगे बढ़ा रहा है, वह इस देश के नागरिकों के बुनियादी अधिकारों और मानवाधिकारों को कुचलकर ही आगे बढ़ सकता है।

यही कारण है कि पूरी कोशिश यही हो रही है कि अधिकार प्राप्त नागरिकों को आज्ञापालक प्रजा में तब्दील कर दिया जाएं, ताकि वे कोई सवाल खड़े न करें, किसी भी प्रकार के अधिकारों की बात न करें और बिना किसी ना–नुकूर के मालिकों की तिजोरियों को भरने का श्राष्ट्रीय कर्तव्य पूरा करते रहे। आज्ञापालक प्रजा असहमति व्यक्त नहीं करती, केवल कर्तव्य का पालन करती है। वह देशद्रोही नहीं, पूरी तरह राष्ट्रभक्ति का अंधानुसरण करती है। पूंजीवाद की कॉर्पोरेट व्यवस्था में नागरिक केवल श्मालश होते है, जिनकी मुनाफा पैदा करने के यज्ञ में आहुति ही दी जानी है।

राहुल सांकृत्यायन होते, तो यही कहते कि रू ऐसे सुप्रीम कोर्ट का क्षय हो!

(टिप्पणीकार अखिल भारतीय किसान सभा से संबद्ध छत्तीसगढ़ किसान सभा के उपाध्यक्ष हैं। संपर्क रू 94242–31650)

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

संपादकीय

शक्ति और साधना

संपादक – राज कुमार

नवरात्रि भारत के सबसे पवित्र और आध्यात्मिक रूप से प्रेरणादायक त्योहारों में से एक है। यह पर्व नौ रातों और दस दिनों तक चलता है और देवी दुर्गा के नौ स्वरूपों की आराधना को समर्पित होता है। नवरात्रि केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह जीवन में शक्ति, अनुशासन और आत्म–परिवर्तन का भी संदेश देता है। यह त्योहार हमें यह समझने का अवसर देता है कि सच्ची शक्ति केवल बाहरी नहीं, बल्कि आंतरिक भी होती है, जो हमारे विचारों, आचरण और मूल्यों में प्रकट होती है। नवरात्रि का मूल भाव 'शक्ति' की उपासना है, जिसे सृष्टि की आधारशिला माना गया है। देवी दुर्गा के प्रत्येक स्वरूप में अलग–अलग गुणों का समावेश है, जैसे साहस, ज्ञान, समृद्धि और पवित्रता। इन गुणों की पूजा केवल धार्मिक अनुष्ठान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमें अपने जीवन में इन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देती है। यह पर्व हमें यह सिखाता है कि व्यक्ति को अपने भीतर छिपी शक्तियों को पहचानकर उन्हें सकारात्मक दिशा में उपयोग करना चाहिए। नवरात्रि का एक महत्वपूर्ण संदेश बुराई पर अच्छाई की विजय है। देवी दुर्गा द्वारा महिषासुर का वध इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म अंततः विजय प्राप्त करते हैं। आज के समय में यह संदेश और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, जब व्यक्ति को अपने भीतर की नकारात्मक प्रवृत्तियों जैसे क्रोध, लोभ और अहंकार से संघर्ष करना पड़ता है। यह त्योहार हमें आत्मचिंतन का अवसर देता है और यह सिखाता है कि आंतरिक शुद्धता और सकारात्मक सोच से ही जीवन में सच्ची सफलता प्राप्त की जा सकती है। नवरात्रि अनुशासन और संयम का भी पर्व है। इस दौरान अनेक लोग व्रत रखते हैं, नियमित पूजा–अर्चना करते हैं और सात्विक जीवनशैली अपनाते हैं। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं, बल्कि शारीरिक और मानसिक शुद्धि का माध्यम भी है। व्रत रखने से शरीर का शोधन होता है और ध्यान तथा भक्ति से मन को शांति मिलती है। यह समय व्यक्ति को अपने भीतर झांकने और आत्मिक संतुलन स्थापित करने का अवसर प्रदान करता है। सांस्कृतिक दृष्टि से नवरात्रि अत्यंत रंगीन और उत्साहपूर्ण पर्व है। देश के विभिन्न हिस्सों में इसे अलग–अलग तरीकों से मनाया जाता है। विशेष रूप से गुजरात में गरबा और डांडिया जैसे पारंपरिक नृत्य इस त्योहार की पहचान हैं। इन आयोजनों में लोग एकत्रित होकर आनंद और उल्लास के साथ भाग लेते हैं, जिससे सामाजिक एकता और सांस्कृतिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। नवरात्रि के दौरान सजे हुए पंडाल, संगीत, नृत्य और भक्ति का वातावरण भारतीय संस्कृति की समृद्धता को दर्शाता है। इस पर्व का एक महत्वपूर्ण पहलू महिला सशक्तिकरण भी है। देवी के रूप में नारी की पूजा करके समाज में महिलाओं के सम्मान और गरिमा को मान्यता दी जाती है। यह त्योहार हमें यह संदेश देता है कि महिलाआ. ं का समाज में महत्वपूर्ण स्थान है और उनके बिना किसी भी समाज की प्रगति संभव नहीं है। आज के समय में जब लैंगिक समानता एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना हुआ है, नवरात्रि इस दिशा में सकारात्मक सोच को प्रोत्साहित करता है। नवरात्रि पर्यावरण और सामाजिक जिम्मेदारी का भी संदेश देता है। आजकल पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए लोग पर्यावरण अनुकूल तरीकों से इस पर्व को मनाने पर जोर दे रहे हैं। प्राकृतिक सामग्री से बनी मूर्तियों का उपयोग और अपशिष्ट को कम करना इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं। इसके साथ ही जरूरतमंदों की सहायता करना और दान–पुण्य करना इस पर्व के आध्यात्मिक महत्व को और बढ़ाता है। अंततः नवरात्रि केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि आत्मिक जागरण और आत्मविकास की एक यात्रा है। यह हमें विश्वास, अनुशासन और सकारात्मकता के माध्यम से जीवन की चुनौतियों का सामना करना सिखाता है। यदि हम इस पर्व के वास्तविक संदेश को अपने जीवन में अपनाएं, तो न केवल हम स्वयं को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि समाज में भी एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं।

जिम्मेदारों का गैरजिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार

जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षो इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है।

M,- jktUæ çlkn 'kekZ

विरोध के नाम विरोध या सत्ता के लालच में राष्ट्र–हित के नकार का कोई उदाहरण मिल सकता है तो वह हमारे देश में ही मिल सकता है। आज जब समूची दुनिया संकट के दौर से गुजर रही है और अमेरिका व ईरान युद्ध के दुष्परिणामों से दुनिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रुप से प्रभावित हो रहे हैं उस दौर में देश में अराजकता का माहौल बनाये जाने के प्रयासों को किसी भी हालात में स्वीकार नहीं किया जा सकता है। समझ में नहीं आता कि देश में भय और अराजकता का माहौल बनाने से क्या हासिल हो सकेगा। आज दुनिया के देशों की एक दूसरे पर निर्भरता अधिक बढ़ी है। ऐसे में दुनिया के किसी भी कौने में कोई अप्रिय घटनाएं घटित होती है तो उसका प्रभाव कमोबेस दुनिया के अन्य देशों पर भी पड़ता है। सबको मालूम है कि कच्चे तेल और एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर निर्भरता कोई आज की बात नहीं है। यह कोई हमारे देश की ही समस्या हो ऐसा भी नहीं है। बल्कि हार्मुज जलडमरुमध्य से जल यातायात को बाधित होने से यह समस्या और अधिक बढ़ी है। यह भी मालूम है कि ताजिंदगी के लिए किसी भी वस्तु की किसी भी देश द्वारा संग्रहण नहीं किया जा सकता। यदि एलपीजी के हालिया संकट की ही बात की जाये तो होना तो यह चाहिए था कि ऐसे संकट के दौर में पक्ष–विपक्ष एक साथ खड़ा होता और ऐसे हालातों में आमजनता को पेनिक करने के स्थान पर हालात से निपटने में सहभागी बनते तो एक जिम्मेदार पक्ष–विपक्ष या आम नागरिक की बात होती। पर हमने तो हालात ऐसे बना दिए जैसे एलपीजी का अकाल आ गया हो और चारों तरफ आंदोलन–प्रदर्शन के हालात बनाकर जमाखोरों को प्रोत्साहित करने और आमजन में भय का वातावरण बना दिया। जिसके घर में एलपीजी का सिलेण्डर था भी वह भी एक और सिलेंडर लाने की दौड़ में लग गया और इससे हालात बनने के स्थान पर बिगड़ने वाले होने लगे। होना तो यह चाहिए था कि विपक्षी भी सरकार के साथ खड़े होकर एक और आम जनता को हालात से निपटने के लिए प्रेरित करते वहीं दूसरी और ऐसे समन्वित प्रयास किये जाते जिससे विदेशों से एलपीजी लाने में आ रही दिक्कतों का हल खोजा जा सकता। गैरजिम्मेदारान हरकत तो इसी से समझा जा सकता है कि सरकार के प्रयासों से जब एलपीजी के दो जहाज होर्मुज जलडमरुमध्य से आने लगे तो यहां तक कहा जाने लगा कि इन जहाजों पर झण्डा अवश्य भारत का है पर इनमें उपलब्ध एलपीजी तो किसी अन्य देश के लिए है। धरने प्रदर्शन और हालात को बदतर बनाने के प्रयास किसी भी हालत में देशहित या देशवासियों के हित में नहीं कहे जा सकते। भले ही यह समझते हो कि हम देशवासियों के हित में सरकार को घेर रहे हैं। सही मायने में देखा जाए तो यह सरकार को घेरना नहीं अपितु देश के प्रति अपने दायित्वों से हटने और पूरी तरह से गैरजिम्मेदाराना गतिविधि ही कही जानी चाहिए।

यह वहीं भारत देश है जब लाल बहाद. ुर शास्त्री के समय अन्न संकट आया तो एक आह्वान पर छोटे बड़े सभी ने एक दिन सोमवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया। पुरानी पीढ़ी के कुछ लोग आज भी उस आह्वान के चलते आज भी सोमवार का व्रत करते हुए मिल जाएंगे। यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 1971 के बांग्लादेश के युद्ध के समय समूचा देश इन्दिरा गांधी के साथ एक स्वर में स्वर मिला रहा था। आज पता नहीं ऐसे हालात कैसे होने लगे हैं कि ऑपरेशन सिन्दुर, सर्जिकल स्ट्राइक या अन्य सैन्य गतिविधियों पर भी प्रश्न उठाये जाने लगे हैं। संभवतः दुनिया के किसी भी देश में इस तरह की बात नहीं होती होगी। जहां तक एलपीजी की बात है तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि एक समय था जब एलपीजी कनेक्शन के लिए वर्षो इंतजार करना पड़ता था। सामान्य परिस्थितियों में भी सिलेंडर प्राप्त करने के लिए लंबी कतारों से भी दो चार होना पड़ता था। धरातल पर देखेंगे तो हालात की गंभीरता को इसी से समझा जा सकता है कि आज 31.3 मिलियन टन एलपीजी गैस की खपत है। देश में 31 करोड़ सक्रिय एलपीजी धरेलू कनेक्शन है। समूचे देश की बात की जाए तो प्रतिदिन ओसतन 50 से 60 लाख एलपीजी सिलेंडर की आवश्यकता होती है। ऐसे में मांग और आपूर्ति बनाये रखना अपने आप में दुष्कर है पर हालिया संकट को अलग कर दिया जाए तो पिछले कुछ सालों से एलपीजी या पेट्रोल आदि को लेकर देश में किसी तरह का संकट देखने को नहीं मिला। विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हार्मुज जलडमरुमध्य से दो जहाज भारतीय तट पर पहुंच चुके हैं। सरकार द्वारा भारतीय जहाजों को निर्बाध रुप से रास्ता दिलाने के प्रयास जारी है। ऐसे हालातों के बावजूद सकारात्मक परिणाम प्राप्त होना बड़ी बात है।

इस संकट के दौर में सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे आना देश के प्रत्येक नागरिक का दायित्व हो जाता है। हालात हमारे सामने हैं, सरकार के प्रयास भी हमारे सामने हैं, ऐसे में जमाखोरी और कालाबाजारी को निरुत्साहित करना हम सबका दायित्व होना चाहिए।

आवश्यकता नहीं होने पर भी जबरदस्ती सिलेण्डर का स्टॉक करने से बचना चाहिए। वितरण व्यवस्था को सुचारु बनाये रखने में सहभागी बनना चाहिए। जब तक हालात सामान्य नहीं होते हैं तब तक जबरदस्ती पेनिक होने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही ऐसे तत्व जो हालात को व्यवस्थित करने के स्थान पर बिगाडने व पेनिक करने व जमाखोरी और कालाबाजारी को प्रोत्साहित कर रहे हो उन्हें बेनकाब करने के लिए आगे आना होगा। यदि ऐसे दौर में हमें एक जुट होना होगा और राष्ट्रहित को ही सर्वोपरी मानना होगा।

– डॉ. राजेन्द्र प्रसाद शर्मा

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू–कश्मीर में संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही पर सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज किया

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू–कश्मीर के राजौरी, डोडा और पुंछ जिलों में सुरक्षा बलों ने संदिग्ध आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना के बाद व्यापक तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मंगलवार देर रात राजौरी जिले के पालमा के पास खंडली और उसके आसपास के इलाकों में एक स्थानीय निवासी द्वारा दो संदिग्ध व्यक्तियों की आवा. जाही की सूचना दी गई। इस सूचना के बाद तुरंत तलाशी अभियान शुरू किया गया और आसपास के इलाके और जंगल क्षेत्रों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की गतिविधियों का पता लगाया गया।

सूचना के अनुसार, संदिग्ध व्यक्तियों को एक नाले के पास देखा गया, जो जंगल की ओर जा रहे थे। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को सील कर दिया और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की निगरानी शुरू कर दी। हालांकि, अभी तक संदिग्ध व्यक्तियों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। अधिकारियों ने बताया कि यह अभियान व्यापक पैमाने पर चलाया जा रहा है और इसमें पुलिस, सेना और अन्य सुरक्षा एजेंसियां शामिल हैं। डोडा जिले के मरमत क्षेत्र में भी तलाशी अभियान जारी है।

स्थानीय लोगों ने इस क्षेत्र में आतंकवादियों की आवाजाही की सूचना दी थी। मरमत इलाके को आतंकवादी डोडा और उधमपुर के बसंतगढ़ के बीच आवागमन के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह मार्ग रामबन जिले के कुछ हिस्सों से भी जुड़ा हुआ है, जिससे आतंकवादियों के हाइडिंग और मूवमेंट को ट्रैक करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। सुरक्षा बल इस क्षेत्र में अतिरिक्त चौकसी बरत रहे हैं और संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी कर रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पुंछ जिले के दांडी धारा और अरी सरूटी क्षेत्र में भी तलाशी अभियान चलाया गया। इन इलाकों में पिछले कुछ समय से संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिल रही थी। स्थानीय लोगों की मदद से सुरक्षा बल आतंकवादियों की संभावित छिपने की जगहों पर छापेमारी कर रहे हैं। सभी ऑपरेशन सतर्कता के साथ किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा खामी न रहे और संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ने में सफलता मिल सके।

पुलिस और सेना ने स्थानीय समुदाय के लोगों से सहयोग मांगा है और उन्हें सतर्क रहने की हिदायत दी है। अधिकारियों ने कहा कि स्थानीय लोगों की सूचनाएँ तलाशी अभियान में अहम भूमिका निभा रही हैं। सुरक्षा बल यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि इलाके में रहने वाले नागरिक सुरक्षित रहें और किसी तरह की हिंसक घटना न हो।

राजौरी, डोडा और पुंछ जिलों में पिछले कुछ महीनों में आतंकवादी गतिविधियों में वृद्धि देखी गई है। सुरक्षा बल लगातार सतर्कता बनाए हुए हैं और इलाके में निगरानी बढ़ाई गई है। अधिकारियों ने बताया कि इस तरह की तलाशी अभियान से आतंकवादियों के आवागमन पर नियंत्रण रखने में मदद मिलती है और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित होती है।

सुरक्षा बलों ने बताया कि अभियान का उद्देश्य केवल संदिग्ध व्यक्तियों को पकड़ना नहीं है, बल्कि संभावित आतंकवादी नेटवर्क को भंग करना और आतंकवादी गतिविधियों को रोकना भी है। इसके तहत इलाके में सभी संभावित छिपने की जगहों, जंगलों और नालों में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

साथ ही, आसपास के गाँवों और कस्बों में चौकसी बढ़ाई गई है।

अधिकारियों ने यह भी कहा कि तलाशी अभियान में आधुनिक तकनीक और जासूसी उपकरणों का उपयोग किया जा रहा है। ड्रोन, निगरानी कैमरा और सेंसर तकनीक की मदद से संदिग्ध व्यक्तियों की मूवमेंट को ट्रैक किया जा रहा है।

इससे अभियान की सफलता की संभावना बढ़ रही है। स्थानीय लोगों ने भी सुरक्षा बलों के अभियान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा बलों की सतर्कता और समय पर कार्रवाई से आतंकवादियों की गतिविधियों को रोकने में मदद मिल रही है।

लोगों ने अधिकारियों से अनुरोध किया है कि तलाशी अभियान जारी रखा जाए ताकि इलाके में सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

इस अभियान के दौरान पुलिस और सेना ने इलाके में ड्राइविंग, पैदल गश्त और नाकाबंदी की व्यवस्था भी की है। अधिकारियों ने बताया कि अभियान के दौरान किसी भी संदिग्ध वस्तु या गति. विधि की तुरंत रिपोर्ट की जाएगी। सभी सुरक्षा उपायों का उद्देश्य आतंकवादियों को किसी भी प्रकार की योजना को अंजाम देने से रोकना और स्थानीय लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है।

इस प्रकार, जम्मू–कश्मीर के राजौरी, डोडा और पुंछ जिलों में सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे व्यापक तलाशी अभियान ने इलाके में आतंकवादी गतिविधियों पर कड़ी नजर बनाए रखी है। स्थानीय लोगों की मदद और आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल से अभियान को सफलता की उम्मीद है और यह इलाके में सुरक्षा और शांति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

जम्मू के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर भीड़ प्रबंधन के लिए स्काउट्स और गाइड्स तैनात किए गए हैं

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : अधिकारियों ने बुधवार को बताया कि नवरात्रि उत्सव के दौरान यात्रियों की सुचारू आवाजाही और भीड़ प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए जम्मू मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों पर स्काउट्स एंड गाइड्स की विशेष टीमें तैनात की गई हैं। उन्होंने बताया कि

श्री माता वैष्णो देवी मंदिर में दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए, मंडल ने स्टेशनों पर अत्यधिक भीड़ से निपटने के लिए व्यापक सुरक्षा और यात्री सुविधा उपाय लागू किए हैं। अधिकारियों ने बताया कि त्योहार के दौरान जम्मू तवी और श्री माता वैष्णो देवी कटरा सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों की भारी भीड़ देखी जाती है।

इसलिए, तीर्थयात्रियों की सहायता और व्यवस्था बनाए रखने के लिए इन स्थानों पर प्रशिक्षित स्काउट्स और गाइड्स तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि

उनकी जिम्मेदारियों में प्लेटफार्मों और प्रवेश एवं निकास द्वारों पर कतारों को व्यवस्थित करना, यात्रियों को सही प्लेटफार्म और ट्रेनों तक पहुंच. ाना, बुजुर्गों, महिलाओं और दिव्यांगजनों की सहायता करना और निर्बाध आवागमन सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट क्षेत्रों में भीड़भाड़ को रोकना शामिल है। उन्होंने बताया कि स्वयंसेवक रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) और सरकारी रेलवे पुलिस (जीआरपी) के साथ समन्वय कर रहे हैं ताकि भीड़ के दबाव के कारण उत्पन्न होने वाली चिकित्सा आपात स्थितियों और अन्य मुद्दों का समाधान किया जा सके। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उचित सिंघल ने कहा कि स्काउट्स और गाइड्स की तैनाती यात्रियों की आवाजाही को सुचारू बनाने और विशेष रूप से बुजुर्ग यात्रियों को ट्रेन से संबंधित आवश्यक जानकारी प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

रेलवे प्रशासन ने तीर्थयात्रियों से धैर्य बनाए रखने, अधिक सामान न ले जाने और रेलवे कर्मचारियों, स्काउट्स, गाइड्स और सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों का पालन करने की अपील की है।

अधिकारियों ने आगे कहा कि यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। चौत्र नवरात्रि 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च को समाप्त होगी, और श्राइन बोर्ड को देश भर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ की उम्मीद है।

केंद्र सरकार के अनुसार, पिछले पांच वर्षों में एक करोड़ से अधिक जन शिकायतें प्राप्त हुई

सबका जम्मू कश्मीर

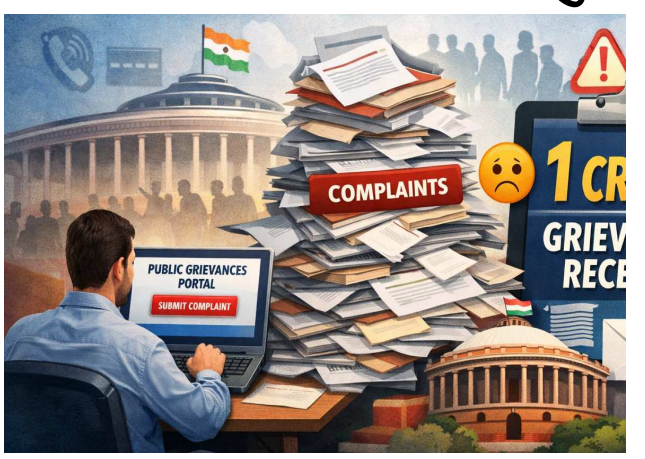

नई दिल्ली : लोकसभा को बुधवार को बताया गया कि पिछले पांच वर्षों में 1 करोड़ से अधिक सार्वजनिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

ये शिकायतें केंद्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम्स) पर प्राप्त हुईं, जो नागरिकों को ऑनलाइन शिकायतें दर्ज करने की अनुमति देती है।

केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री जित. ेंद्र सिंह ने लिखित जवाब में कहा कि 2021 से फरवरी 2026 के बीच 1,11,89,384 जन शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 2021 में 20,00,590 शिकायतें प्राप्त हुईं, 2022 में 19,18,238 और 2023 में 19,53,057 शिकायतें प्राप्त हुईं।

उन्होंने कहा कि अगले दो वर्षों में क्रमशः 26,15,321 और 22,78,256 शिकायतें प्राप्त हुईं, और इस वर्ष जनवरी और फरवरी के बीच 4,23,922 शिकायतें दर्ज की गईं।

मंत्री ने कहा, ष्वर्ष 2025 में, केंद्रीय सरकारी मंत्रालयों/विभागों के लिए सार्वजनिक शिकायतों के निपटान का औसत समय 15 दिन था, और 82.1: शिकायतों का निपटान 21 दिनों की निर्धारित समय सीमा के भीतर किया गया।ष

उन्होंने कहा कि प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) मासिक समीक्षा बैठकों के माध्यम से मंत्रालयों, विभागों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिकायत निपटान प्रदर्शन की नियमित रूप से समीक्षा करता है। सिंह ने कहा, षजिन मंत्रालयों/विभागों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में अधिक मामले लंबित हैं या देरी हो रही है, उन्हें सुधारात्मक उपाय करने की सलाह दी जाती है।ष

उन्होंने कहा कि सरकार ने शिकायत निवारण तंत्र की जवाब. देही और दक्षता में सुधार के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें 10–चरणीय सुधारों का कार्यान्वयन भी शामिल है।

इसके अलावा, सिंह ने कहा कि अगस्त 2024 में जारी सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देशों ने शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया है और समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, मूल कारण विश्लेषण पर जोर, नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करने को अनिवार्य बनाया है।

उन्होंने बताया कि सार्वजनिक शिकायतों की वरिष्ठ स्तर पर समीक्षा को सुगम बनाने के लिए सीपीग्राम्स में एक समीक्षा बैठक मॉड्यूल भी शुरू किया गया है।

पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच भारत पहुंचा तेल व एलपीजी, मुंद्रा और वडीनार बंदरगाह पर लोडिंग

सबका जम्मू कश्मीर

अहमदाबाद : अधिकारियों ने बताया कि पश्चिम एशिया संघर्ष के बीच, भारतीय ध्वज वाला टैंकर जग लाडकी लगभग 80,886 मीट्रिक टन कच्चे तेल के साथ बुधवार को गुजरात के मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा।

एक दिन पहले, एलपीजी ले जाने वाला जहाज नंदा देवी होर्मुज जलडमरूमध्य से होते हुए 46,500 मीट्रिक टन द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) लेकर गुजरात के देवभूमि द्वारका जिले के वडीनार बंदरगाह पर पहुंचा था। सोमवार को, एलपीजी ले जाने वाला एक अन्य जहाज – शशिवालिकश – मुंद्रा बंदरगाह पर पहुंचा। मुंद्रा बंदरगाह का संचालन करने वाली अदानी पोर्ट्स ने एक बयान में कहा कि जग लाडकी द्वारा लाया गया कच्चा तेल संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से प्राप्त किया गया था और वहां के फुजैराह बंदरगाह पर लोड किया गया था। "कुल लंबाई 274.19 मीटर और चौड़ाई 50.04 मीटर वाले इस टैंकर का डेडवेट टन भार लगभग 164,716 टन और ग्रॉस टन भार लगभग 84,735 टन है," इसमें कहा गया है। टैंकर का मुंद्रा बंदरगाह पर आगमन कच्चे तेल के भारी आयात को संभालने में इस सुविधा की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित करता है।

"यह डिलीवरी उन प्रमुख रिफाइनरियों का समर्थन करती है जो परिचालन बनाए रखने और क्षेत्र में आपूर्ति में व्यवधान के दौरान भारत

की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ऐसे शिपमेंट पर निर्भर करती हैं," अदानी पोर्ट्स ने आगे कहा।

बंदरगाह ने पोत को सुरक्षित बर्थिंग प्रदान की और भारत की महत्वपूर्ण ऊर्जा लाइनों की सुरक्षा में समुद्री समन्वय प्रदान किया। संयुक्त अरब अमीरात के फुजैराह बंदरगाह को इजरायल–अमेरिका और ईरान युद्ध के दौरान ड्रोन और मिसाइल हमलों का सामना करना पड़ा। भारत अपनी लगभग 88 प्रतिशत कच्चे तेल, 50 प्रतिशत प्राकृतिक गैस और 60 प्रतिशत एलपीजी की जरूरतों का आयात करता है।

28 फरवरी को अमेरिका और इज़राइल द्वारा ईरान पर किए गए हमले और तेहरान की जवाबी कार्रवाई से पहले, भारत के कच्चे तेल के आयात का आधे से अधिक, लगभग 30 प्रतिशत गैस और 85–90 प्रतिशत एलपीजी आयात सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे मध्य पूर्वी देशों से होता था। इस संघर्ष के कारण खाड़ी देशों से ऊर्जा आपूर्ति के मुख्य पारगमन मार्ग, होर्मुज जलडमरूमध्य की नाक. बंदी कर दी गई है।

हालांकि भारत ने रूस सहित अन्य देशों से तेल प्राप्त करके कच्चे तेल की आपूर्ति में आई बाधाओं की कुछ हद तक भरपाई कर ली है, लेकिन औद्योगिक उपयोगकर्ताओं को गैस की आपूर्ति कम हो गई है और होटल और रेस्तरां जैसे व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में एलपीजी की उपलब्धता घट गई है।

इजरायल के हमले में ईरान के सुरक्षा प्रमुख की मौत के बाद ईरान ने इजरायल और खाड़ी देशों पर हमला किया

सबका जम्मू कश्मीर

दुबई : ईरान ने बुधवार तड़के इजरायल और पड़ोसी खाड़ी देशों की ओर हमले किए, जिनकी आवाजें संयुक्त अरब अमीरात और कतर में सुनी गईं और सऊदी अरब में कुछ सिग्नल इंटरसेप्ट किए जाने की खबरें आईं। ये हमले ईरानी सरकारी मीडिया द्वारा इस बात की पुष्टि करने के कुछ घंटों बाद हुए कि इजरायल की सेना ने रात भर चले हमले में शीर्ष ईरानी सुरक्षा अधिकारी अली लारीजानी और साथ ही विरोध प्रदर्शनों को दबाने में अपनी भूमिका के लिए जाने जाने वाले रिवोल्यूशनरी गार्ड के बासिज बल के प्रमुख जनरल गुलाम रजा सुलेमानी को मार गिराया। इजरायली हवाई हमले में बेरूत के मध्य में स्थित बाचौरा में एक अपार्टमेंट इमारत को तड़के ही ध्वस्त कर दिया गया। लेबनानी स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, बुधवार तड़के बेरूत के अन्य इलाकों में आवासीय अपार्टमेंटों पर हुए दो हमलों में कम से कम छह लोग मारे गए और 24 अन्य घायल हो गए। हाल के दिनों में, इजरायल द्वारा बेरूत के मध्य भाग को निशाना बनाकर किए जाने वाले हमले, पूर्व सूचना के साथ या बिना पूर्व सूचना के, लगातार बढ़ते जा रहे हैं। ये हमले शहर के दक्षिणी उपनगरों से काफी दूर तक फैले हुए हैं, जिनके लिए सेना ने हिजबुल्लाह के साथ युद्ध की शुरुआत में ही निकासी के नोटिस जारी कर दिए थे।

ईरान के साथ अमेरिका–इजरायल युद्ध में ईरान में कम से कम 1,300, लेबनान में 900 से अधिक और इजरायल में 14 लोग मारे गए हैं, इन देशों के अधिकारियों के अनुसार। अमे. रिकी सेना का कहना है कि 13 अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं और लगभग 200 घायल हुए हैं।

ये रही ताज़ा जानकारी :

हिजबुल्लाह के अल–मनार टीवी के पत्रकार की इजरायली हवाई हमले में मौत हो गई।

अल–मनार ने कहा कि उसके राजनीतिक कार्यक्रम के प्रमुख मोहम्मद शेरी और उनकी पत्नी की बेरूत के मध्य में स्थित ज़ोकाक ब्लाट इलाके पर हुए हमले में मौत हो गई।

अल–मनार ने बताया कि बुधवार तड़के हुए हमले में शेरी के बच्चे और पोते–पोतियां घायल हो गए।

शेरी कई वर्षों से उस स्टेशन पर प्रस्तुतकर्ता थीं और देश भर में काफी जानी–पहचानी थीं।

इराक ने तुर्की के रास्ते किरकुक तेल का निर्यात फिर से शुरू किया।

इराक ने बुधवार को कहा कि उसने किरकुक शहर के तेल क्षेत्रों से पाइपलाइन के माध्यम से तुर्की के सेहान बंदरगाह तक तेल निर्यात फिर से शुरू कर दिया है।

इराकी तेल मंत्रालय ने कहा कि यह घटनाक्रम इराकी सरकार द्वारा देश के उत्तर में स्थित स्वायत्त कुर्द प्रशासन के साथ एक समझौते पर पहुंचने के बाद सामने आया है।

इस कदम से फारस की खाड़ी से पूरी तरह बचा जा सकेगा। मंत्रालय ने कहा कि वह शुरुआत में प्रतिदिन 250,000 बैरल कच्चे तेल का निर्यात करेगा।

मध्य पूर्व में युद्ध और होर्मुज जलडमरूमध्य के लगभग बंद होने से इराक बुरी तरह प्रभावित हुआ है, जिसकी अर्थव्यवस्था काफी हद तक तेल पर निर्भर है।

बहरीन पर मिसाइल और ड्रोन हमले, इज़राइल में सायरन बजने की आवाज

बहरीन ने बुधवार को कहा कि ईरान ने उस द्वीप राज्य पर एक मिसाइल और एक ड्रोन दागा है, जहां अमेरिकी पांचवीं नौसेना का बेड़ा तैनात है।

इसी बीच, उत्तरी इजराइल के कुछ हिस्सों में आने वाली मिसाइलों की चेतावनी देते हुए सायरन बजने लगे हैं।

लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि मध्य बेरूत पर इजरायली हवाई हमलों में 10 लोग मारे गए। मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि आधी रात के आसपास शुरू हुए हवाई हमलों में 27 लोग घायल भी हुए हैं।

इसमें कहा गया है कि 2 मार्च को इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच लड़ाई का नवीनतम दौर शुरू होने के बाद से लेबनान में 912 लोग मारे गए हैं और 2,221 लोग घायल हुए हैं।

तंबाकू की तस्करी के प्रयास के बाद इज़राइल ने गाजा को यूनिसेफ की सहायता सामग्री की आपूर्ति रोक दी।

इजरायल की सैन्य संस्था सीओजीएटी, जो गाजा को सहायता पहुंचाने के समन्वय का जिम्मा संभालती है, ने बुधवार को कहा कि उसने एक दिन पहले केरेम शालोम सीमा पर यूनिसेफ की सहायता सामग्री की खेप का निरीक्षण करते समय स्वच्छता किटों के अंदर तंबाकू और निकोटीन उत्पाद पाए।

टिप्पणी के अनुरोध पर यूनिसेफ ने तत्काल कोई जवाब नहीं दिया।

सीओजीएटी के मेजर जनरल योरम हालेवी ने कहा कि यूनिसेफ द्वारा इस मामले पर प्रतिक्रिया दिए जाने तक निलंबन जारी रहेगा।

अक्टूबर 2023 में युद्ध शुरू होने के बाद से इजराइल ने गाजा में सहायता और वाणिज्यिक वस्तुओं के प्रवेश पर कड़ा नियंत्रण रखा है, लेकिन तस्कर किसी न किसी तरह से सामान पहुंचाने में कामयाब हो जाते हैं।

फारूक अब्दुल्ला पर हमला : जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जनता से वीडियो, फोटो और सबूत मांगे

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर पुलिस ने एक जन सूचना जारी कर उन लोगों से सूचना, वीडियो रिकॉर्डिंग और तस्वीरें मांगी हैं जो उस विवाह समारोह में उपस्थित थे जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला पर जानलेवा हमला हुआ था। पुलिस ने रविवार को ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में बुधवार को एक विवाह समारोह में अब्दुल्ला पर हुई गोलीबारी की घटना की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया। रेंज मुख्यालय जम्मू–सांबा–कठुआ द्वारा जारी नोटिस के अनुसार, डीआईजी शिव कुमार शर्मा ने समारोह में उपस्थित सभी मेहमानों, आम जनता या घटना से संबंधित डिजिटल साक्ष्य या जानकारी रखने वाले किसी भी व्यक्ति से इसे जांच एजेंसी के साथ साझा करने की अपील की है। उन्होंने कहा, ष्इसके लिए दिए गए संपर्क नंबर 9419150173, 9419131379 और 9419186210 हैं।ष डीआईजी ने बताया कि यह घटना 11 मार्च को जम्मू के ग्रेटर कैलाश स्थित रॉयल पार्क में एक शादी समारोह के दौरान हुई थी। गंग्याल पुलिस स्टेशन ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल (एसआईटी) का गठन किया गया है।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जनता का सहयोग एसआईटी को महत्वपूर्ण सबूत जुटाने और पारदर्शी जांच सुनिश्चित करने में काफी मददगार होगा। जम्मू जोन के पुलिस महानिरीक्षक (आईजीपी) भीम सेन तुती ने रविवार को मामले की षांभीरता और संवेदनशीलताष को देखते हुए जम्मू–सांबा–कठुआ रेंज के पुलिस उप महानिरीक्षक की देखरेख में एसआईटी के गठन का आदेश दिया। पिछले बुधवार की रात, पूर्व मुख्यमंत्री अब्दुल्ला बाल–बाल बच गए जब ग्रेटर कैलाश क्षेत्र के रॉयल पार्क बैंक्वेट हॉल में एक शादी समारोह से निकलते समय एक बंदूकधारी ने उन पर पीछे से गोली चला दी। 63 वर्षीय आरोपी, जिसकी पहचान कमल सिंह के रूप में हुई है, को मौके पर ही काबू कर गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से अपराध में इस्तेमाल किया गया एक रिवॉल्वर बरामद किया गया।

जम्मू-कश्मीर सरकार हर नागरिक को सस्ती स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है : स्वास्थ्य मंत्री इटू

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : स्वास्थ्य मंत्री सकीना इटू ने बुधवार को कहा कि जम्मू और कश्मीर सरकार केंद्र शासित प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को समान, समावेशी और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है।

इटू ने दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले के चावलगाम में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का उद्घाटन किया। लगभग 74 लाख रुपये की अनुमानित लागत से निर्मित यह अस्पताल, आधुनिक स्वास्थ्य सेवाओं के साथ–साथ पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार के निरंतर प्रयासों में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उद्घाटन समारोह के बाद अपने संबोधन में मंत्री ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार की गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने की प्रतिबद्धता पर बल दिया।

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आयुष प्रणालियों को पारंपरिक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने से न केवल उपचार के विकल्प बढ़ेंगे, बल्कि समय–परीक्षित स्वदेशी उपचार पद्धतियों को पुनर्जीवित और संस्थागत रूप भी मिलेगा। "सरकार हर नागरिक को समान, समावेशी और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के अपने मिशन के प्रति दृढ़ संकल्पित है। इस अस्पताल का उद्घाटन एक मजबूत और विविध स्वास्थ्य प्रणाली के हमारे दृष्टिकोण को दर्शाता है जो परंपराओं का सम्मान करते हुए नवाचार को अपनाती है," उन्होंने कहा।

इटू ने बताया कि नवस्थापित सुविधा आयुर्वेद, योग, यूनानी और होम्योपैथी (आयुष) के तहत व्यापक और एकीकृत उपचार पद्धतियां प्रदान करेगी, जिससे कुलगाम और आसपास के क्षेत्रों के लोगों को सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित होगी।

निवारक स्वास्थ्य देखभाल के महत्व पर प्रकाश डालते हुए, इटू ने कहा कि आयुष जीवनशैली प्रबंधन, पुरानी बीमारियों की देखभाल और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

उन्होंने आगे कहा कि यह अस्पताल स्वास्थ्य जागरूकता, सामुदायिक संपर्क कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण पहलों के केंद्र के रूप में भी काम करेगा। उन्होंने कहा, "यह 50 बिस्तरों वाला अस्पताल सुसज्जित इनपेशेंट वार्ड, विशेषीकृत आउटपेशेंट विभाग, पंचकर्म चिकित्सा इकाइयां, निदान सुविधाएं, योग और स्वास्थ्य केंद्र तथा समर्पित परामर्श कक्षों से युक्त है ताकि उच्च स्तर के उपचार और रोगी देखभाल सुनिश्चित की जा सके।"

मंत्री ने कहा कि कम सुविधा प्राप्त और ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवा अवसंरचना को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

साप्ताहिक सबका जम्मू कश्मीर

गुलमर्ग पट्टा मामला : पक्षकारों द्वारा सरकारी समाधान का विकल्प चुनने पर उच्च न्यायालय ने याचिकाएं बंद कीं

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय ने गुलमर्ग के होटलों की भूमि पट्टे से जुड़े हाई–प्रोफाइल मामले में कई रिट याचिकाओं का निपटारा कर दिया है। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के साथ समझौता करने के लिए याचिकाएं वापस लेने का अनुरोध किया था।

मुख्य न्यायाधीश अरुण पल्ली और न्यायमूर्ति रजनेश ओसवाल की पीठ ने इस महीने की शुरुआत में याचिकाकर्ताओं द्वारा विवाद के निपटारे के लिए सरकार से संपर्क करने के इरादे को देखते हुए याचिकाएं वापस लेने की अनुमति दे दी थी। 2022 में, उपराज्यपाल के नेतृत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन ने जम्मू–कश्मीर भूमि अनुदान नियम लागू किए, जो जम्मू–कश्मीर में एक महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव था। नए ढांचे के तहत, पट्टे की अवधि समाप्त होने के बाद उसे बढ़ाने की प्रथा बंद कर दी गई है और ऐसी संपत्तियों को खुली बोली के माध्यम से नीलाम किया जाएगा, जिससे वे किसी भी भारतीय नागरिक के लिए सुलभ हो जाएंगी। इसका प्रभाव विशेष रूप से गुलमर्ग के पर्यटन स्थल में स्पष्ट है, जहां अधिकांश होटल पट्टे पर ली गई भूमि पर बने हैं। 59 होटलों में से 55 के पट्टे समाप्त हो चुके हैं, जिससे मालिकों पर बेदखली और नीलामी का खतरा मंडरा रहा है। उच्च न्यायालय इस मामले की सुनवाई कई बार कर चुका था और याचिकाकर्ताओं के वकीलों ने अपनी दलीलें पूरी कर ली थीं। हालांकि, सुनवाई के दिन अंतिम चरण में याचिकाकर्ताओं के वरिष्ठ वकील जेड ए शाह ने याचिकाएं वापस लेने की अनुम. ति मांगी। वे अदालत में मुकदमा जारी रखने के बजाय पहले सरकार से संपर्क करके प्रतिनिधित्व के माध्यम से विवाद का समाधान करना चाहते थे। सरकार ने वरिष्ठ एएजी मोहसिन कादरी के माध्यम से अदालत को सूचित किया कि वह षनिष्पक्ष, उचित और न्यायसंगतष समाधान के लिए तैयार है और आश्वा. सन दिया कि याचिकाकर्ताओं की सुनवाई के बाद दो सप्ताह के भीतर दायर किए गए किसी भी अभ्यावेदन पर विधिवत विचार किया जाएगा।

इन दलीलों पर ध्यान देते हुए, अदालत ने कहा कि मामले की खूबियों की जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं है और तदनुसार याचिकाओं का निपटारा कर दिया। कई संबंधित अवमानना घ्याचिकाओं को भी निरर्थक मानते हुए निपटा दिया गया, जबकि कुछ रिट याचिकाओं को वकीलों के निर्देश पर वापस ले लिया गया मानकर खारिज कर दिया गया। हालांकि, अदालत ने यह भी कहा कि इस मामले पर पहले ही काफी न्यायिक समय व्यतीत हो चुका है और पक्षों के रुख में बदलाव के कारण कार्यवाही संभवतः समाप्त नहीं हो पाई थी। "उपरोक्त वर्णित स्थिति और संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए बयान के मद्देनजर, हमें मामले की खूबियों पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

तदनुसार, इन सभी याचिकाओं का निपटारा उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है," पीठ के आदेश में कहा गया। "लेकिन इस मामले को समाप्त करने से पहले, हम यह स्पष्ट करना चाहेंगे कि हमने इन याचिकाओं पर कई बार विस्तार से सुनवाई की है और मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के लिए काफी न्यायिक समय लगाया है। और यदि न्यायालय के समक्ष जो परिवर्तित स्थिति सामने आई है, वह न होती, तो संभवतः हम आज ही कार्यवाही समाप्त कर देते," न्यायालय ने कहा।

मंत्रिमंडल ने 2,585 करोड़ रूपये की लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दी

सबका जम्मू कश्मीर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2,585 करोड़ की लघु जलविद्युत विकास योजना को दी मंजूरी

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 2,585 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली लघु जलविद्युत विकास योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना का उद्देश्य देश में 1,500 मेगावाट की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के विकास को बढ़ावा देना है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि यह निर्णय पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत विकसित की जाने वाली परियोजनाएँ बिना किसी बड़े बांध के निर्माण और बिना किसी विस्थापन के नदी के प्रवाह पर आधारित होंगी, जिससे प्राकृतिक संसाधनों और स्थानीय समुदायों पर नकारात्मक प्रभाव न्यूनतम होगा। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि देश में लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए अपार संभावनाएँ मौजूद हैं। भारत में कुल 7,133 स्थलों पर 21,000 मेगावाट की क्षमता वाली लघु जलविद्युत परियोजनाओं की संभावना है। वर्तमान में 1,196 स्थलों पर कुल 5,100 मेगावाट की लघु जलविद्युत परियोजनाएं कार्यरत हैं। इन परियोजनाओं की क्षमता आम तौर पर 1 मेगावाट से 25 मेगावाट तक होती है। योजना के तहत अगले पांच वर्षों, यानी 2030–31 तक, इन परियोजनाआ. ं का विकास और कार्यान्वयन किया जाएगा।

मंत्री ने बताया कि इस योजना के माध्यम से लघु जलविद्युत परियोजनाओं में लगभग 15,000 करोड़ रुपये का निवेश आकर्षित होने की उम्मीद है। यह निवेश न केवल नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करेगा, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन और स्थानीय आर्थिक विकास में भी योगदान देगा। उन्होंने कहा कि लघु जलविद्युत परियोजनाएँ पर्यावरणीय दृष्टि से टिकाऊ हैं और यह देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण कदम है।

वैष्णव ने बताया कि इस योजना में विकसित की जाने वाली परियोजनाओं को नदी के प्राकृ तिक प्रवाह और पर्यावरणीय संत. ुलन को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जाएगा। इससे न केवल पारिस्थितिकी पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि जल संसाधनों का स्थायी उपयोग भी सुनिश्चित होगा। उन्होंने कहा कि ये परियोजनाएँ स्थानीय समुदायों के साथ साझेदारी में विकसित की जाएंगी और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी, ताकि योजना का सामाजिक और आर्थिक लाभ अधि. कतम रूप से प्राप्त हो सके।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लघु जलविद्युत परियोजनाएँ ऊर्जा क्षेत्र में स्वदेशी तकनीक और नवाचार को भी प्रोत्साहित करेंगी। इन परियोजनाओं में छोटे और मध्यम आकार के उपकरण और प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा, जिससे परियोजनाओं की लागत कम होगी और संचालन में दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा, यह योजना देश में ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोता. ं पर निर्भरता कम करने में मदद करेगी। वैष्णव ने यह भी बताया कि इस योजना से ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति में सुधार होगा।

छोटे और मध्यम आकार के जलविद्युत प्रोजेक्ट स्थानीय ऊर्जा आवश्यकता को पूरा करने में सक्षम होंगे और इन क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देंगे। इसके अलावा, यह योजना नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में निवेशक. ों के लिए एक आकर्षक अवसर प्रदान करेगी और निवेश को प्रोत्साहित करेगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लघु जलविद्युत विकास योजना देश के हरित ऊर्जा लक्ष्यों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

नवरात्रि के लिए माता वैष्णो देवी मंदिर में भारी सुरक्षा

सबका जम्मू कश्मीर

कटरा/जम्मू : एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि चौत्र नवरात्रि के लिए त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की ओर जाने वाले मार्ग पर व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है।

श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड (एसएमवीडीएसबी) के सीईओ सचिन कुमार वैश्य ने बताया कि नौ दिवसीय उत्सव से पहले भवन और आसपास के परिसर सहित पूरे मंदिर क्षेत्र को फूलों से सजाया गया है। राम नवमी पर समाप्त होने वाली इस अवधि के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों के आने की उम्मीद है।

"श्राइन बोर्ड ने श्रद्धालुओं की सुविधा, सुरक्षा और सुगम दर्शन के लिए व्यापक व्यवस्था की है। इस वर्ष तीर्थयात्रियों की संख्या 15 लाख तक पहुंच गई है, और माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में यात्रा और बढ़ेगी," वैश्य ने कटरा में पत्रकारों से कहा दृ जो मंदिर आने वाले तीर्थयात्रियों का आधार शिविर है। सीईओ ने बताया कि सीआरपीएफ, जम्मू और कश्मीर पुलिस, श्राइन बोर्ड के सुरक्षा कर्मचारियों और सेना के कर्मियों के साथ बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है उन्होंने बताया कि एक एकीकृत कमांड और कंट्रोल सेंटर चौबीसों घंटे काम कर रहा है और स्थिति पर लगातार नजर रखने के लिए हाई–टेक सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। विभिन्न स्थानों पर आठ श्क्या हम आपकी मदद कर सकते हैंश डेस्क स्थापित किए गए हैं। सीईओ ने कहा कि दिव्यांग श्रद्धालुओं को प्राथमिकता दी जा रही है और पिछले वर्षों की तरह ही उन्हें मुफ्त बैटरी कार सेवा और टट्टू सेवा प्रदान की जाएगी। वैश्य ने बताया कि इस वर्ष कुछ नई सुविधाएं भी जोड़ी गई हैं, जैसे ध्यान के लिए साधना कक्ष और हवन के लिए यज्ञशाला।

जम्मू–कश्मीर के उरी में नदी बचाव अभियान के दौरान मार्कोस कर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर के बारामूला जिले में झेलम नदी में चलाए जा रहे एक बचाव अभियान के दौरान मंगलवार को नौसेना का एक मरीन कमांडो गंभीर रूप से घायल हो गया। अधिकारियों के अनुसार घायल कमांडो को तुरंत उपचार के लिए सेना के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है।

जानकारी के अनुसार यह घटना उस समय हुई जब उरी क्षेत्र में एक महिला द्वारा झेलम नदी में छलांग लगाए जाने के बाद संयुक्त बचाव अभियान चलाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि उक्त महिला, जो उरी के लगमा इलाके की निवासी थी और अधेड़ आयु की थी, ने चंदनवारी क्षेत्र में स्थित एक लकड़ी के पैदल पुल से नदी में कूदकर आत्मघाती कदम उठाया। घटना के तुरंत बाद स्थानीय प्रशासन को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया गया।

अधिकारियों ने बताया कि प्रारंभिक स्तर पर राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल बारामूला और नागरिक सुरक्षा इकाई उरी की टीमों ने मौके पर पहुंचकर तलाशी अभियान शुरू किया। नदी का बहाव तेज होने और क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां चुनौतीपूर्ण होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा।

साप्ताहिक राशिफल

मेष

मेष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कभी खुशी कभी गम लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आपक. ो निजी जीवन से लेकर करियर–कारोबार तक में उतार–चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं। हालांकि सप्ताह की शुरुआत सामान्य रहने वाली है। इस दौरान व्यक्तिगत और पेशेवेर रूप से खुद को मजबूत पाएंगे। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। युवाओं का अधिकांश समय मौज–मस्ती करते हुए बीतेगा। घर–परिवार में मांगलिक कार्य संपन्न होंगे। सप्ताह के मध्य में आपको करियर–कारोबार में कुछ अप्रत्याशित बदलाव को झेलना पड़ सकता है।

इस दौरान नौकरीपेशा लोगों के सिर पर अचानक से अतिरिक्त जिम्मेदारी का बोझ आ सकता है। जिसे पूरा करने के लिए आपको अधिक समय और ऊर्जा खर्च करने की आवश्यकता रहेगी।

वृषभ

वृष राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी है। वृष राशि के जो जातक किसी कार्य विशेष के लिए बीते कुछ समय से लगातार प्रयासरत हैं, उन्हें इस सप्ताह भी उससे जुड़ी सफलता के लिए इंतजार करना पड़ सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले उनका पूर्वार्ध थोड़ा राहत भरा रहने वाला है।

ऐसे में इस राशि के जातकों को अपने करियर–कारोबार और जीवन से जुड़े अहम कार्यों को इसी दौरान करने का प्रयास करना चाहिए। सप्ताह के मध्य में किसी व्यक्ति विशेष से मेल–मुलाकात होगी। जिसकी मदद से अटके कार्यों में धीमी गति से ही लेकिन प्रगति होती नजर आएगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में न सिर्फ कार्यक्षेत्र से जुड़ी बल्कि घर–परिवार से संबंधित समस्याएं भी आपकी परेशानी का कारण बन सकती हैं। इस दौरान पैतृक संपत्ति अथवा किसी जमीन–जायदाद को लेकर विवाद हो सकता है। अचानक से जीवन में तमाम तरह की समस्याएं सामने आने से आपका मन थोड़ा विचलित रह सकता है। हालांकि सुखद पहलू यह है कि इस दौरान आपके संगी–साथी आपकी ढाल बनेंगे और आपके साथ साए की तरह बने रहेंगे।

मिथुन

मिथुन राशि के जातकों को इस सप्ताह सौभाग्य का पूरा साथ मिलेगा। यदि आप किसी कार्य विशेष के लिए लंबे समय से प्रयासरत थे तो उम्मीद का दामन बिल्कुल न छोड़ें क्योंकि इस सप्ताह उसमें आ रही बाधाएं स्वतरू दूर होती हुई नजर आएंगी। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय नौकरीपेशा लोगों के लिए अनुकूल रहने वाला है।

इस दौरान आपके शुभचिंतक आपको नेक सलाह देते हुए नजर आएंगे, जिस पर अमल करके आप अपनी चीजों को सुव्यवस्थित कर सकते हैं। सप्ताह के मध्य में किसी तीर्थ स्थान पर जाने का अचानक प्रोग्राम बन सकता है। इस पूरे सप्ताह घरेलू महिलाओं का मन धार्मिक–कार्यों में खूब रमेगा। किसी धार्मिक–आध्यात्मिक व्यक्ति की विशेष कृपा आप पर बरस सकती है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए सप्ताह के पूर्वार्ध के मुक. ाबले उत्तरार्ध ज्यादा शुभ रहने वाला है। इस दौरान आप आप समझदारी के साथ अपने पैसे का सही जगह निवेश करते हैं तो आपको उससे भविष्य में बड़ा लाभ मिल सकता है। उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लेकर आएगा।

कर्क

कर्क राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिश्रित फलदायक रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को किसी भी फैसले को लेते समय जल्दबाजी करने से बचना चाहिए। रिश्ते–नाते में मिठास बनी रहे और किसी प्रकार की गलतफहमी न पैदा हो इसके लिए स्वजनों के साथ संवाद बनाए रखें।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार के सिलसिले में बड़े फैसले लेने पड़ सकते हैं। ऐसा करते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में सीनियर और जूनियर को मिलाकर चलें। यदि कार्यक्षेत्र पर हालात आपके अनुकूल नहीं हैं तो आप उससे बजाय भागने के उसे बेहतर बनाने का प्रयास करें। भूलकर भी आवेश में आकर नौकरी में बदलाव जैसा फैसला लेने से बचें। सप्ताह के मध्य में घरेलू समस्याओं के चलते आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा। इस दौरान आपको आपके विरोधी आप पर हावी होने तथा आपके बनते काम बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं।

सिंह

सिंह राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मध्यम फलदायी रहने वाला है। इस सप्ताह इस राशि के जातक. ों को अपनी ऊर्जा, धन और समय का प्रबंधन करके चलना उचित रहेगा। सप्ताह की शुरुआत में आपके सिर पर अचानक से कुछ बड़े खर्च आ सकते हैं। इस दौरान कार्य विशेष के लिए लंबी दूरी की यात्रा पर भी अचानक निकलना पड़ सकता है। यात्रा सुखद और नये संपर्कों को बढ़ाने वाली साबित होगी। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह के उत्तरार्ध के मुकाबले पूर्वार्ध का समय ज्यादा अनुकूल रहने वाला है। ऐसे में आपको अपने कारोबार से जुड़े बड़े फैसले इसी दौरान करने चाहिए। सप्ताह के मध्य में आप कुछ चीजों को लेकर खुद को असमंजस की स्थिति में पा सकते हैं। ऐसे में इस दौरान कोई बड़ा फैसला लेते समय अपने शुभचिंतकों की सलाह अवश्य लें। नौकरीपेशा जातकों इस सप्ताह अपने कार्य दूसरों के भरोसे छोड़ने की बजाय स्वयं बेहतर तरीके से पूरे करने का प्रयास करना चाहिए अन्यथा पूर्व में की गई न सिर्फ आपकी मेहनत बेकार जा सकती है, बल्कि वरिष्ठ अधिकारियों की डांट भी सुननी पड़ सकती है।

कन्या

कन्या राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। यदि आप चाहते हैं कि आपको जीवन में मनचाही सफलता और खुशियां मिले तो आपको अपने कार्य और व्यवहार में आमूलचूल बदलाव लाना होगा और अपने शुभचिंतकों को नाराज करने से बचना होगा। इस सप्ताह आपकी किसी बात या व्यवहार से आपके अपने नाराज हो सकते हैं। वाद–विवाद बढ़ने पर वर्षों से बने रिश्ते में दरार आ सकती है। करियर–कारोबार से लेकर घर–परिवार में सब कुछ अच्छा बना रहे इसके लिए दूसरों से अपेक्षा करने करने की बजाय आपको खुद ही आगे बढ़कर प्रयास करना होगा।

यदि आप नौकरीपेशा व्यक्ति हैं तो अपने कार्यक्षेत्र में कनिष्ठ लोगों के साथ रुखा व्यवहार न करें और अपने वरिष्ठ लोगों के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। यदि आप व्यवसायी हैं तो शार्टकट तरीके से लाभ कमाने से बचें और कागजी काम पूरे करके रखें। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो धन का लेनदेन सावधानी के साथ करें।

तुला

तुला राशि के जातकों के लिए करियर और कारोबार की दृष्टि से यह सप्ताह उत्तम और रिश्ते–नाते की दृष्टि से मध्यम फलदायी रहने वाला है।

सप्ताह की शुरुआत में आपको करियर–कारोबार से जुड़ा कोई बहुप्रतीक्षित शुभ समाचार प्राप्त हो सकता है। इस सप्ताह तुला राशि का नौकरीपेशा जातक हो या फिर व्यवसाय से जुड़ा कारोबारी, वह अपना शत प्रतिशत अपने कार्य में देता हुआ नजर आएगा।

खास बात कि उसके प्रयासों को सौभाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी और सीनियर आपके कामकाज की खुले मन से प्रशंसा करते हुए नजर आएंगे। सप्ताह के अंत तक आपको बड़ा पद अथवा अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। यदि आप लंबे समय से किसी नये कारोबार की शुरुआत करने अथवा किसी बड़ी डील को फाइनल करने के लिए प्रयासरत थे तो आपकी यह मनोकामना इस सप्ताह पूरी हो सकती है। यदि आप लंबे समय से रोजी–रोजगार के लिए प्रयासरत थे तो सप्ताह के उत्तरार्ध में आपकी यह मनोकामना पूरी हो सकती है।

वृश्चिक

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए है। इस सप्ताह आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शुभता–सफलता की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह आपके सोचे हुए कार्य समय पर पूरे होंगे। करियर–कारोबार में मनचाही प्रगति होती नजर आएगी। कार्यक्षेत्र में आपको सीनियर और जूनियर दोनों का सहयोग और समर्थन मिलेगा। व्यवसाय में अच्छा मुनाफा कमाएंगे। यदि आपके कारोबार में बीते समय से कोई अड़चन आ रही थी इस सप्ताह वह किसी व्यक्ति विशेष की मदद से दूर हो जाएगी। मार्केट में आपकी साख बढ़ेगी। यदि आप साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो आप उसके विस्तार की योजना पर काम करेंगे। आपकी योजना को साकार रूप देने के लिए आपके शुभचिंतक और परिजन पूरी मदद करेंगे। इस संबंध में घर–परिवार के किसी वरिष्ठ सदस्य की सलाह लाभदायी साबित होगी। यह सप्ताह पठन–पाठन एवं शोध से जुड़े कार्यों को करने वालों के लिए अत्यधिक शुभ साबित होगा।

धनु

धनु राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह जीवन के नये अवसरों को लेकर आने वाला है, लेकिन उसका लाभ उठाने के लिए आपको आलस्य और आशंका को त्याग कर कठिन परिश्रम और प्रयास करना होगा। इस सप्ताह यदि आप अपने धन, समय और उर्जा का सही दिशा में उपयोग करते हैं तो आपको आशा से अधिक सफलता और लाभ मिल सकता हैं। वहीं इसकी अनदेखी करने पर बनते काम बिगड़ जाने से मन में निराशा के भाव जाग सकते हैं। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह खुले हाथ धन खर्च करने से बचना चाहिए अन्यथा सप्ताह के अंत तक उन्हें उधार मांगने की नौबत आ सकती है। व्यवसाय की दृष्टि से यह सप्ताह आपके लिए मिश्रित फलदायी साबित होने वाला है। इस सप्ताह आपको कारोबार में लाभ तो होगा लेकिन साथ ही साथ खर्च की अधिकता भी बनी रहेगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह मौसमी बीमारी को लेकर सतर्क रहने की आवश्यकता रहेगी। अपनी दिनचर्या और खानपान सही रखें अन्यथा पेट संबंधी दिक्कतें हो सकती है। परीक्षा–प्रतियोगिता की तैयारी में जुटे छात्रों को सप्ताह के मध्य में किसी सुखद समाचार की प्राप्ति संभव है।

मकर

मकर राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह उतार–चढ़ाव लिए रहने वाला है। इस सप्ताह आप अपने करियर–कारोबार में आ रही अड़चनों को लेकर चिंतित रह सकते हैं। कार्यक्षेत्र और कारोबार के अलावा निजी जीवन से जुड़ी समस्याएं भी आपकी बड़ी चिंता का कारण बनेंगी। हालांकि जीवन के कठिन समय में आपके शुभचिंतक एवं परिजन काफी मददगार साबित होंगे और काफी हद तक आप इन समस्याओं का समाधान खोजने में भी कामयाब होंगे। सप्ताह के मध्य में किसी भी कार्य को करते समय विशेष सावधानी बरतें। इस दौरान जल्दबाजी या असमंजस की स्थिति में लिया गया निर्णय आपके लिए हानिकारक साबित हो सकता है। इस दौरान स्वजनों के साथ बात–व्यवहार करते समय विनम्रता से पेश आएं अन्यथा लंबे समय से बने हुए रिश्तों में दरार आ सकती है। इस सप्ताह खर्च की अधि. कता के चलते आपका बजट थोड़ा गड़बड़ा सकता है। सप्ताह के उत्तरार्ध में करियर–कारोबार के सिलसिले में लंबी दूरी की यात्रा पर निकलना पड़ सकता है।

कुंभ

जीवन में आने वाली छोटी–मोटी दिक्कतों को यदि नजरअंदाज कर दें तो कुंभ राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपको आपकी मेहनत का पूरा फल प्राप्त होगा। करियर और कारोबार की दिशा में किए गये प्रयास सफल होंगे और आपके पद एवं प्रतिष्ठा में बढ़ोत्तरी होगी।

राजनीति से जुड़े लोगों के लिए यह सप्ताह गुडलक लिए हुए है। इस सप्ताह आपकी झोली में कोई बड़ा पद गिर सकता है। सत्तापक्ष से जुड़े लोगों के साथ आपका मेल–मिलाप बढ़ेगा। आपके मान–सम्मान में बढ़ोत्तरी होगी। नौकरीपेशा लोगों को कार्यक्षेत्र में अनुकूलता बनी रहेगी। आप अपनी सूझबूझ से अपने विरोधियों पर काबू पाने में कामयाब होंगे। कुंभ राशि के जो जातक तकनीक के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इसी प्रकार इलेक्ट्रानिक का कारोबार करने वालों को बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। सप्ताह के उत्तरार्ध में किसी वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति से कार्य विशेष के लिए मार्गदर्शन प्राप्त होगा।

मीन

मीन राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह मिलाजुला रहने वाला है। सप्ताह के पूर्वार्ध का समय जहां अनुकूल तो वहीं उत्तरार्ध थोड़ा प्रतिकूल रहने वाला है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों सप्ताह की शुरुआत में ही निबटाने का प्रयास करना चाहिए। यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको इसी दौरान पूरे मनोयोग से रोजी–रोजगार के लिए प्रयास करना चाहिए। इस दौरान किसी व्यक्ति विशेष की मदद से भूमि–भवन से जुड़े विवाद का समाधान निकल सकता है। मीन राशि के जातकों को इस सप्ताह इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनकी बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ भी सकती है।

ऐसे में अपना काम निकलवाने के लिए लोगों की प्रशंसा करने में जरा भी कंजूसी न करें और सभी के साथ अच्छा तालमेल बनाए रखें। सप्ताह के पूर्वार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक अथवा मांग. लिक कार्यक्रम संपन्न हो सकता है। इस दौरान घरेलू महिलाओं का अधिकांश समय पूजा–पाठ में बीतेगा।

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

डॉ. अजय कुमार टिक्कू को जम्मू-कश्मीर के आयुष विभाग के निदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : जम्मू और कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक हित में डॉ. अजय कुमार टिक्कू को आयुष विभाग (जम्मू और कश्मीर) का अतिरिक्त प्रभार सौंपने का निर्णय लिया है। सरकारी आदेश संख्या 157–जेके (एचएमई) 2026 दिनांक 18 मार्च के अनुसार, डॉ. टिक्कू वर्तमान में डोडा में प्रभारी जिला आयुष अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं और अब उन्हें अपने नियमित कर्तव्यों के साथ–साथ आयुष विभाग के निदेशक का प्रभार भी संभालना होगा। आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि डॉ. टिक्कू तत्काल प्रभाव से इन जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे और उनके वेतन तथा ग्रेड के अनुसार सभी प्रशासनिक कर्तव्यों को पूरा करेंगे। आयुष विभाग का अतिरिक्त प्रभार संभालने के साथ ही डॉ. टिक्कू को विभागीय नीतियों, योजनाओं और कार्यक्रमों के समन्वय और संचालन की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में विभाग की योजनाओं को प्रभावी ढंग से लागू करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच बढ़ाने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा, वे विभाग के कर्मचारियों और स्वास्थ्य केंद्रों के प्रबंधन, प्रशिक्षण और कार्यकुशलता की निगरानी भी करेंगे।

डॉ. टिक्कू की नियुक्ति से यह उम्मीद जताई जा रही है कि आयुष विभाग के कार्यकुशल संचालन और नीति निर्माण में नई ऊर्जा और दृष्टिकोण आएगा। उनके अनुभव और प्रशासनिक कौशल का लाभ विभागीय योजनाओं और कार्यक्रमों के बेहतर कार्यान्वयन में मिलेगा। वर्तमान समय में आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की आवश्यकता और महत्व लगातार बढ़ रहा है, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं की पहुंच सीमित है। ऐसे में डॉ. टिक्कू के नेतृत्व में विभाग ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आयुष सेवाओं को अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने की दिशा में कदम उठाएगा।

आदेश के अनुसार, डॉ. टिक्कू अपने अतिरिक्त प्रभार के साथ सभी प्रशासनिक, वित्तीय और नियामक कर्तव्यों का पालन करेंगे। इसमें विभागीय बजट का प्रबंधन, योजना तैयार करना, कार्यक्रमों का कार्यान्वयन और स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण का समन्वय शामिल है। उनके मार्गदर्शन में विभाग नई नीतियाँ और योजनाएँ लागू करेगा, जिससे प्रदेश में आयुष सेवाओं की गुणवत्ता और पहुंच दोनों में सुधार होगा। डॉ. टिक्कू की नियुक्ति को अधिकारियों और कर्मचारियों ने सकारात्मक कदम के रूप में देखा है। उनका अनुभव, नेतृत्व क्षमता और विभागीय कार्यों में उनकी कुशलता इसे सुनिश्चित करेगी कि विभाग के सभी योजनाओं और कार्यक्रमों का कार्यान्वयन समयबद्ध और प्रभावी रूप से हो। इसके साथ ही जनता तक आयुष स्वास्थ्य सेवाओं की बेहतर और आसान पहुंच सुनिश्चित होगी।

इस निर्णय से यह भी संकेत मिलता है कि जम्मू और कश्मीर सरकार स्वास्थ्य और आयुष सेवाओं के क्षेत्र में सुधार और विस्तार के लिए गंभीर प्रयास कर रही है। डॉ. टिक्कू की नियुक्ति से विभागीय कार्यप्रणाली में नई गति आएगी और विभिन्न स्वास्थ्य योजनाओं और कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू करने में मदद मिलेगी। इस प्रकार, डॉ. टिक्कू अपने अतिरिक्त प्रभार के माध्यम से आयुष विभाग को नई दिशा देने और प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता और उपलब्धता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जम्मू-कश्मीर में बजट सत्र 27 मार्च को फिर से शुरू होने पर उत्तरी कैरोलिना भूमि अनुदान विधेयक पेश करेगी

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) आगामी बजट सत्र में भूमि अनुदान विधेयक 2025 पेश करने की योजना बना रही है। यह बजट सत्र 27 मार्च को जम्मू में फिर से शुरू होगा। पार्टी प्रवक्ता और विधायक तनवीर सादिक ने बताया कि इस विधेयक का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को उनकी भूमि अधिक. ार वापस दिलाना है। सादिक ने इसे ष्अत्यंत महत्वपूर्णष बताते हुए कहा कि 2022 में किए गए संशोधनों के कारण गरीबों के भूमि अधिकार प्रभावित हुए थे और अब उन्हें पुनः सुरक्षित करने की जरूरत है।

सादिक ने पत्रकारों से कहा कि आगामी सत्र में कई विधेयक प्रस्तुत किए जाएंगे, जिनमें सरकारी और निजी सदस्यों के विधेयक शामिल होंगे। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका यह भूमि अनुदान विधेयक अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह आर्थिक रूप से कमजा. ेर वर्गों की भूमि से संबंधित है और पहले किए गए संशोधनों को पलटने की आवश्यकता है। उन्होंने जोर देते हुए कहा, ष्यह विधेयक गरीबों की जमीन वापस दिलाने और उनके अधिकार सुरक्षित करने के लिए है। 2022 में जो संशोधन हुआ, उससे गरीबों की जमीन प्रभावित हुई थी। अब हमें उनके अधिकार वापस देने होंगे। सादिक ने अक्टूबर में हुए पिछले विधानसभा सत्र का भी उल्लेख किया, जब पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के वहीद पारा द्वारा पेश किए गए भूमि अनुदान विधेयक को जम्मू–कश्मीर सरकार ने खारिज कर दिया था। उन्होंने कहा कि आगामी सत्र में सदस्यों द्वारा पेश किए गए कई अन्य विधेयकों पर भी विचार किया जाएगा और उनका उद्देश्य सभी विधेयकों को पारदर्शी और न्यायसंगत तरीके से चर्चा के लिए प्रस्तुत करना है।

सादिक ने इस दौरान शराब पर किसी संभावित विधेयक के बारे में पूछे जाने पर अपनी व्यक्तिगत राय व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वे व्यक्तिगत रूप से शराब पर प्रतिबंध के पक्षधर हैं। उन्होंने कहा, ″अगर आप मुझसे व्यक्तिगत रूप से पूछें, तो शराब पर प्रतिबंध होना चाहिए।

वाराणसी में गंगा तट पर इफ्तार आयोजित करने और बिरयानी खाने के आरोप में 14 लोग गिरफ्तार

सबका जम्मू कश्मीर

वाराणसी (उत्तर प्रदेश) : अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि गंगा नदी पर एक नाव में इफ्तार करते हुए बिरयानी खाते हुए कथित तौर पर प्रदर्शित एक वीडियो के बाद, पूजा स्थल को अपवित्र करने और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में चौदह लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई भाजपा युवा मोर्चा की नगर इकाई के प्रमुख रजत जायसवाल द्वारा सोमवार को दर्ज कराई गई लिखित शिकायत पर की गई।

जायसवाल ने आरोप लगाया कि गंगा में एक नाव पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जिसमें बिरयानी खाई गई थी। उन्होंने कहा,

″सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए गंगा में गहरी और अटूट आस्था है। देश और दुनिया भर से हजारों श्रद्धालु प्रतिदिन काशी में आकर गंगाजल से पूजा–अर्चना करते हैं।

पुलिस स्टेशन

बाग-ए-बहू	2459777
बख्शी नगर	2580102
बस स्टैंड	2575151
शहर	2543688
गांधी नगर	2430528
गंग्याल	2482019
नौबाद	2571332
पक्का डांगा	2548610
रेलवे स्टेशन	2472870
सैनिक कॉलोनी	2462212
सतवारी	2430364
चन्नी हिम्मत	2465164
ट्रांसपोर्ट नगर	2475444
त्रिकुटा नगर	2475133
गांधी नगर	2459660
एसएसपी शहर	2561578
एसपी शहर उत्तर	2547038
एसपी दक्षिण	2433778

सार्वजनिक उपयोगिता सेवाएँ

इंडियन एयर लाइन्स	
शहर कार्यालय	2542735
एयर पोर्ट	2430449
जेट एयर वेज़	2453999
सिटी ऑफिस	2573399

रेलवे

रेलवे पूछताछ	131, 132, 2476407
बुकिंग	2470318
आरक्षण	2470315

पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग स्टेशन

बख्शी नगर	2543557
गांधी नगर	2430786
कंपनी बाग	2542582
नया प्लॉट	2573429
पंजतीर्थी	2547537

दूरसंचार विभाग

डायरेक्टरी पूछताछ	197
फॉल्ट रिपेयर	198
ट्रंक बुकिंग	180
बिलिंग शिकायत	2543896

जम्मू नगर पालिका

जं. लाइन्स	2578503
प्रशासन अधिकारी	2542192
स्वास्थ्य अधिकारी	2547440

डाक सेवाएँ

मुख्य डाकघर शहर	2543606
गाँधी नगर	2435863

अग्निशमन सेवाएँ

नियंत्रण कक्ष	101,132, 2476407
शहर	2544263
गाँधी नगर	2457705
नहर	2554064
गंग्याल	2480026

रसोई गैस डीलर

चिनाब गैस	2547633
गुलमौर गैस	2430835
जैकफेड	2548297
एचपी गैस	2578456
शिवांगी गैस	2577020
तवी गैस	2548455

पावर हाउस

गाँधी नगर	2430180
नहर रोड	2554147
जानीपुर	2533828
नानक नगर	2430776

परेड	2542289
सतवारी कैंट	2452813

अस्पताल

जीएमसी अस्पताल	2584290
एस.एम.जी.एस. अस्पताल	2547635
सी.डी. अस्पताल	2577064
डैंटल अस्पताल	2544670
गांधी नगर अस्पताल	2430041
सरवाल अस्पताल	2579402
जी.बी. पंत कैंट अस्पताल	2433500
आयुर्वेदिक कॉलेज	2543661
सी.आर.पी. अस्पताल	2591105
आचार्य श्री चंदर	2662536
मानसिक अस्पताल	2577444
स्वामी विवेकानंद	2547418
ब्लड बैंक	2547637
एम्बुलेंस	2584225, 2575364
एम्बुलेंस (रेड क्रॉस)	2543739

नर्सिंग होम

मदन अस्पताल	2456727
मेडिकेयर	2435070
त्रिवेणी नर्सिंग होम	2452664
सुविधा नर्सिंग होम	2555965
अल. फिरदौस नर्सिंग होम	2545050
आस्था नर्सिंग होम	2576707
बी एन चैरिटेबल ट्रस्ट	2505310
चोपड़ा नर्सिंग होम	2573580
हरबंस सिंह मेम हॉस्पिटल	2541952
जीवन ज्योति	2576985
युद्धवीर नर्सिंग होम	2547821
मीडियाएड नर्सिंग होम	2466744
सीता नर्सिंग होम	2435007
विभूति नर्सिंग होम	2547969
रामेश्वर नर्सिंग होम	2580601
बी एन चेरिटेबल	2555631
महर्षि दयानंद	2545225

काबुल अस्पताल पर हमले की भारत ने की कड़ी निंदा, क्षेत्रीय शांति पर खतरे की चेतावनी

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : भारत ने अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में स्थित ओमिद नशा मुक्ति अस्पताल पर पाकिस्तान द्वारा किए गए कथित हवाई हमलों की तीखी निंदा करते हुए इसे कायरतापूर्ण और अमानवीय हिंसा का कृत्य करार दिया है।

विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को जारी एक विस्तृत बयान में कहा कि इस प्रकार का हमला न केवल अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानूनों का उल्लंघन है, बल्कि निर्दोष नागरिकों के जीवन के प्रति पूर्ण उपेक्षा को भी दर्शाता है।

मंत्रालय के अनुसार यह हमला सोमवार रात 16 मार्च को किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में आम नागरिकों की जान चली गई। बयान में स्पष्ट रूप से कहा गया कि जिस अस्पताल को निशाना बनाया गया, वह किसी भी दृष्टि से सैन्य लक्ष्य नहीं हो सकता था। इस प्रकार के हमले को किसी भी स्थिति में उचित नहीं ठहराया जा सकता। मंत्रालय ने यह भी आरोप लगाया कि पाकिस्तान अब इस घटना को सैन्य कार्रवाई का रूप देने की कोशिश कर रहा है, जो वास्तविकता से परे है।

अफगानिस्तान में तालिबान प्रशासन ने दावा किया है कि इस हमले में कम से कम चार सौ लोगों की मौत हो गई और ढाई सौ से अधिक लोग घायल हुए हैं। यह आंकड़ा इस घटना की भयावहता को दर्शाता है। घायलों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी शामिल बताए जा रहे हैं, जिससे यह स्पष्ट होता है कि हमला सीधे तौर पर नागरिकों को प्रभावित करने वाला था। हालांकि पाकिस्तान ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि उसने केवल सैन्य ठिकानों और तथाकथित आतंकवादी ढांचे को निशाना बनाया था और किसी अस्पताल पर हमला नहीं किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि यह हमला अफगानिस्तान की संप्रभुता पर सीधा प्रहार है और इससे पूरे क्षेत्र की शांति एवं स्थिरता को गंभीर खतरा उत्पन्न होता है। मंत्रालय ने कहा कि इस प्रकार की कार्रवाई न केवल अस्वीकार्य है, बल्कि यह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के मूल सिद्धांतों के भी विरुद्ध है। भारत ने यह भी कहा कि इस घटना से पाकिस्तान के उस रवैये का पता चलता है, जिसमें वह अपनी आंतरिक समस्याओं और विफलताओं को छिपाने के लिए सीमाओं के पार हिंसक गति. विधियों का सहारा लेता रहा है।

बयान में आगे कहा गया कि अंतरराष्ट्रीय समुदाय को इस मामले को गंभीरता से लेना चाहिए और दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए ठोस कदम उठाने चाहिए। भारत ने वैश्विक मंचों से यह भी आग्रह किया कि अफगानिस्तान में नागरिकों को निशाना बनाने वाली ऐसी घटनाओं को तत्काल रोका जाए और भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए प्रभावी तंत्र विकसित किया जाए।

भारत ने इस दुखद घटना में जान गंवाने वाले लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। साथ ही, भारत ने यह भी दोहराया कि वह इस कठिन समय में अफगानिस्तान के लोगों के साथ एकजुटता से खड़ा है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि भारत अफगानिस्तान की संप्रभुता, स्वतंत्रता और क्षेत्रीय अखंडता का दृढ़ता से समर्थन करता है और इस सिद्धांत से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि यह घटना क्षेत्र में पहले से मौजूद तनाव को और बढ़ा सकती है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच संबंध पहले से ही तनावपूर्ण रहे हैं और इस प्रकार की घटनाएं दोनों देशों के बीच अविश्वास को और गहरा कर सकती हैं।

रमजान के पवित्र महीने के दौरान इस तरह की हिंसा ने स्थिति को और संवेदनशील बना दिया है, जिससे क्षेत्रीय शांति के लिए चुनौतियां बढ़ गई हैं।

इस बीच, अंतरराष्ट्रीय समुदाय की प्रतिक्रिया पर भी नजरें टिकी हुई हैं। कई देशों और संगठनों से उम्मीद की जा रही है कि वे इस घटना की निष्पक्ष जांच की मांग करेंगे और यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेंगे कि जिम्मेदार पक्षों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए।

कुल मिलाकर यह घटना न केवल मानवीय दृष्टिकोण से बेहद दुखद है, बल्कि यह क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए भी गंभीर चिंता का विषय बन गई है। भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि वह इस प्रकार की हिंसा के खिलाफ अपनी आवाज उठाता रहेगा और शांति, स्थिरता तथा मानवता के पक्ष में मजबूती से खड़ा रहेगा।

जम्मू में स्टाफ क्वार्टर परियोजना का निरीक्षण, समय पर पूरा करने के निर्देश

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल विभाग की सचिव अवनी लवासा ने सोमवार को जम्मू के कैनाल रोड स्थित सर्किट हाउस के समीप निर्माणाधीन स्टाफ क्वार्टर परियोजना का विस्तृत निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने कार्य की प्रगति, गुणवत्ता और समयबद्धता का जायजा लेते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा–निर्देश दिए।

यह परियोजना लगभग 3.43 करोड़ रुपये की लागत से एसएएससीआई योजना के अंतर्गत क्रियान्वित की जा रही है और इसे चालू वित्त वर्ष के अंत तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। अधिकारियों ने जानकारी दी कि परियोजना का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है, जिससे यह स्पष्ट है कि निर्माण कार्य अंतिम चरण में है। इस परियोजना के तहत विभागीय कर्मचारियों के लिए 12 दो बेडरूम वाले आधुनिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं, जो कर्मचारियों को बेहतर आवासीय सुविधा प्रदान करेंगे।

निरीक्षण के दौरान सचिव अवनी लवासा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर संतोष व्यक्त किया, लेकिन साथ ही यह भी निर्देश दिया कि शेष कार्य को तय समय सीमा के भीतर पूर्ण किया जाए। उन्होंने कार्यकारी अभियंता और निर्माण एजेंसी को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि परियोजना का भौतिक और वित्तीय दोनों रूपों में समुचित समापन वित्त वर्ष की समाप्ति से पहले सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना न केवल संसाधनों के प्रभावी उपयोग को दर्शाता है, बल्कि इससे कर्मचारियों को समय पर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती हैं।

उन्होंने यह भी जोर दिया कि निर्माण कार्य के अंतिम चरण में गुणवत्ता से किसी प्रकार का समझौता नहीं किया जाना चाहिए। सभी आवश्यक सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य को पूरी सावधानी और जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जाए, ताकि कर्मचारियों को सुरक्षित और आरामदायक आवास उपलब्ध हो सके। निरीक्षण के पश्चात सचिव ने विभाग के अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक भी आयोजित की। इस बैठक में विभाग से संबंधित विभिन्न प्रशासनिक और प्रबंधन संबंधी मुद्दों पर विस्तार से चर्चा की गई। विशेष रूप से विभाग के पुनर्गठन, मानव संसाधन प्रबंधन और कार्यप्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के उपायों पर विचार–विमर्श किया गया।

बनी तहसील में बर्फबारी और बारिश से जनजीवन प्रभावित, बनी–बदरवाह मार्ग बंद

सबका जम्मू कश्मीर

बनी/कठुआ। जम्मू–कश्मीर के बनी तहसील के दूरदराज इलाकों में लगातार हो रही बर्फबारी और बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर दिया है। मौसम में अचानक आए बदलाव के कारण ठंड एक बार फिर तेज हो गई है, जिससे लोगों को कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में तापमान गिरने के साथ ही सामान्य गतिविधियां भी प्रभावित हो गई हैं। बर्फबारी और बारिश के चलते बनी–बद्रवाह सड़क पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया है। इसके अलावा कई संपर्क सड़कें भी बाधित हो गई हैं, जिससे गांवों के बीच आपसी संपर्क टूट गया है। स्थानीय लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मरीजों और आपात स्थिति में फंसे लोगों के लिए स्थिति और अधिक चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

मंडी गुट्टू, सरथल, नुकनाली, छत्रगला, वासुकी नाग स्थान, डगर और लोहाई मल्हार जैसे क्षेत्रों में भारी बर्फबारी दर्ज की गई है। इन इलाकों में जनजीवन लगभग ठहर सा गया है और लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। लगातार हो रही बर्फबारी के कारण बनी–बद्रवाह मार्ग पर अभी तक यातायात बहाल नहीं हो पाया है, जिससे यात्रियों और स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन द्वारा सड़कों को बहाल करने के प्रयास लगातार जारी हैं। मशीनों और कर्मचारियों की मदद से बर्फ हटाने का कार्य तेजी से किया जा रहा है, ताकि जल्द से जल्द सामान्य स्थिति बहाल हो सके।

यह सबके लिए फायदेमंद है, केंद्र ने सार्थक बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है : वांगचुक ने अपनी रिहाई पर यह बात कही

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : जेल से रिहा होने के बाद अपने पहले सार्वजनिक संबोधन में कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने मंगलवार को राष्ट्रीय सुरक्षा प्रतिबंध (एनएसए) के तहत अपनी हिरासत रद्द किए जाने को ष्सभी पक्षों के लिए फायदेमंदष् घटनाक्रम बताया और कहा कि केंद्र सरकार ने लद्दाख के लोगों के साथ सार्थक बातचीत के लिए विश्वास का हाथ बढ़ाया है।

अपनी पत्नी और एचआईएएल की सह–संस्थापक गीतांजलि जे आंगमो के साथ यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए वांगचुक ने कहा कि लद्दाख में विरोध प्रदर्शन का एकमात्र उद्देश्य रचनात्मक संवाद प्रक्रिया शुरू करना था।

उन्होंने कहा, ष्हमें अदालत में जीत का पूरा भरोसा था, लेकिन जीत ही काफी नहीं

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

बनी क्षेत्र में अनोखी परंपरा : शारदीय के साथ-साथ चौत्र नवरात्र में भी होता है भगवान राम के जीवन का मंचन

राज कुमार

कठुआ जिले के पहाड़ी क्षेत्र बनी में धार्मिक परंपराओं का अनोखा संगम देखने को मिलता है। जहां पूरे देश में आमतौर पर शारदीय नवरात्रि के दौरान ही रामलीला या राम नाटक क्लबों द्वारा भगवान राम के जीवन का मंचन किया जाता है, वहीं बनी क्षेत्र इस परंपरा को अलग पहचान देता है।

बनी के विभिन्न इलाकों में शारदीय नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक राम नाटक क्लबों की ओर से भगवान राम के जीवन, उनके आदर्शों और घटनाओं को मंच पर प्रस्तुत किया जाता है। श्रद्धालु बड़ी संख्या में इन कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और भक्ति भाव से राम कथा का आनंद लेते हैं।

खास बात यह है कि बनी के धार डुगनु क्षेत्र में चौत्र नवरात्रि के दौरान भी 7 दिनों तक भगवान राम की महिमा का गुणगान किया जाता है। यहां भी मंचों पर राम के जीवन से जुड़ी घटनाओं का जीवंत प्रदर्शन किया जाता है, जो इसे देश के अन्य हिस्सों से अलग बनाता है।

स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ निभाई जाती है। बनी क्षेत्र की यह अनोखी धार्मिक विरासत न केवल आस्था का प्रतीक है, बल्कि सांस्कृतिक पहचान को भी मजबूत करती है।

राजौरी में मीटर रीडर रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार

सबका जम्मू कश्मीर

श्रीनगर : जम्मू–कश्मीर भ्रष्टाचार–विरोधी ब्यूरो ने मंगलवार को बताया कि उन्होंने राजौरी स्थित पीडीडी में तैनात एक मीटर रीडर को एक शिकायतकर्ता से बिजली का बढ़ा हुआ बिल कम करने के बदले 30,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है।

प्रवक्ता ने बताया कि जम्मू–कश्मीर भ्रष्टाचार–विरोधी ब्यूरो ने पीडीडी राजौरी में मीटर रीडर के पद पर तैनात आरिफ इकबाल के खिलाफ एफआईआर संख्या 03/2026 के तहत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 में संशोधित) की धारा 7 के तहत 17 मार्च, 2026 को पीएस एसीबी राजौरी में मामला दर्ज किया है। यह मामला शिकायतकर्ता की शिकायत पर आधारित है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि शिकायतकर्ता वर्ष 2019 से 2021 तक टायर की दुकान चला रहा था, जिसके बाद उसकी दुकान बंद हो गई।

"उनके पास बिजली का कनेक्शन है और वे नियमित रूप से अपना बिजली बिल भरते थे। उन्हें 31.12.2025 से 31.01.2026 की अवधि के लिए ध्2497 का बिजली बिल फरवरी 2026 में प्राप्त हुआ।"

"इस संबंध में, पीडीडी राजौरी के मीटर रीडर आरिफ इकबाल ने शिकायतकर्ता से मुलाकात की और उनसे ध्50,000 देने को कहा ताकि वे उनका बिजली बिल चुका सकें। इस पर शिकायतकर्ता ने कहा कि वे मीटर रीडिंग के अनुसार बिल का भुगतान करेंगे।"

"इसके बाद, उसने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि उसका बिजली का बिल बढ़ा दिया जाएगा। 5 मार्च 2026 को, आरिफ इकबाल फिर आया और 31 जनवरी 2026 से 28 फरवरी 2026 की अवधि का 1,53,890 रुपये का बिजली का बिल दिया, जिसकी भुगतान तिथि 27 मार्च 2026 थी।

जब शिकायतकर्ता ने उससे इतने अधिक बिल के बारे में पूछा, तो आरिफ इकबाल (मीटर रीडर) ने बिल समायोजित करने के लिए 50,000 रुपये रिश्वत के रूप में मांगे। बाद में, बातचीत के बाद यह राशि 30,000 रुपये कर दी गई," प्रवक्ता ने बताया।

उन्होंने आगे बताया कि शिकायतकर्ता उपर्युक्त मीटर रीडर को अवैध रिश्वत नहीं देना चाहता था, इसलिए उसने एसीबी राजौरी पुलिस स्टेशन में उपर्युक्त आरिफ इकबाल (मीटर रीडर) के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के लिए लिखित शिकायत दर्ज कराई। प्रवक्ता ने कहा,

"मामला दर्ज होने के बाद, एसीबी पुलिस स्टेशन राजौरी की एक टीम गठित की गई।

जम्मू-कश्मीर में गरीब मजदूर, किसान और बुजुर्ग परेशान - मजदूर दस्तकार यूनियन की सरकार से अपील

रोहित शर्मा

कटरा/जम्मू। जम्मू–कश्मीर में गरीब मजदूर, दस्तकार और किसानों की समस्याएं दिन–प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। कई ऐसे परिवार हैं जिनके बीपीएल राशन कार्ड को एपीएल में बदल दिया गया, जबकि उनकी आर्थिक स्थिति आज भी बेहद कमजोर है। वहीं 70दृ80 वर्ष के बुजुर्गों की पेंशन भी बंद हो चुकी है, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

मजदूर दस्तकार यूनियन ने सरकार से हाथ जोड़कर अपील की है कि गरीबों के राशन कार्ड जल्द बनाए जाएं, बंद पेंशन को बहाल किया जाए और महंगाई पर नियंत्रण किया जाए, ताकि आम गरीब परिवारों को राहत मिल सके।

यूनियन का कहना है कि हाल ही में बारिश और खराब मौसम से भी लोगों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अभी तक प्रभावित परिवारों को पूरा मुआवजा नहीं मिला है। इसके साथ ही

पढ़े–लिखे नौजवान भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। कई परिवारों ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए कर्ज लिया या जमीन तक बेच दी, लेकिन आज वही युवा ओवरएज होकर रोजगार से वंचित हो रहे हैं।

मजदूर दस्तकार यूनियन ने सरकार से मांग की है कि गरीब मजदूरों, किसानों और बेरोजगार युवाओं की समस्याओं का जल्द समाधान किया जाए, ताकि जम्मू–कश्मीर में लोग शांति और सम्मान के साथ अपना जीवन जी सकें।

जितेंद्र सिंह के अनुसार, कक्षा में मौजूद भारतीय उपग्रहों से उत्पन्न होने वाले 129 ट्रैक करने योग्य अंतरिक्ष मलबे हैं

सबका जम्मू कश्मीर

नई दिल्ली : केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने बुधवार को लोकसभा में बताया कि मार्च 2026 तक भारतीय उपग्रह मिशना. ें से उत्पन्न कुल 129 ट्रैक करने योग्य अंतरिक्ष मलबे कक्षा में मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि इस अंतरिक्ष मलबे में निष्क्रिय उपग्रह, रॉकेट अवशेष और अन्य टूटे हुए अवशेष शामिल हैं। मंत्री ने बताया कि निम्न पृथ्वी कक्षा (एलईओ) में 23 निष्क्रिय उपग्रह और भूस्थिर पृथ्वी कक्षा (जीईओ) में 26 निष्क्रिय उपग्रह हैं। इसके अलावा, पीएसएलवी (40), जीएसएलवी (4) और एलवीएम3 (3) रॉकेट के अवशेष भी कक्षा में मौजूद हैं। पीएसएलवी सी3 रॉकेट के अवशेष (33) के कक्षा में टूटने से उत्पन्न मलबा भी शामिल है।

जितेंद्र सिंह ने अंतरिक्ष मलबा हटाने और इसे नियंत्रित करने के लिए भारत

की रणनीति पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि इसरो ने 2024 में मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन (डीएफएसएम) पहल की घोषणा की, जिसका उद्देश्य 2030 तक सभी भारतीय सरकारी और निजी संस्थाओं द्वारा शून्य मलबा उत्पन्न करना है। इस पहल के तहत मिशन डिजाइन और परियोजना आरंभिक चरण में ही अंतरिक्ष यान और प्रक्षेपण यान दोनों के लिए अतिरिक्त ईंधन मार्जिन सुनिश्चित किया जाता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी परिस्थिति में उपग्रह या रॉकेट अवशेष को नियंत्रित करके पृथ्वी की कक्षा से हटाया जा सके।

मंत्री ने बताया कि इसरो सक्रिय मलबा हटाने की तकनीकों पर अध्ययन कर रहा है। इसमें रोबोटिक आर्म, रेंडेज़वस और प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस शामिल हैं। ये तकनीकें अंतरिक्ष मलबा हटाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम हैं और भविष्य में भारतीय अंतरिक्ष मिशना. ें की सुरक्षा सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने बताया कि भारत ने 2025 में स्पैडेक्स मिशन के माध्यम से एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की, जिसमें स्वायत्त रेंडेज़वस, डॉकिंग और अनडॉकिंग क्षमताओं का प्रदर्शन किया गया। इस मिशन के लिए प्रक्षेपण यान के ऊपरी चरण, यानी पीएस4 कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल या पीओईएम–4 प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने योग्य रोबोटिक आर्म और रोबोटिक मैनिपुलेटर का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया।

जितेंद्र सिंह ने कहा कि इन तकनीक. ों के सफल परीक्षण से भारत की अंतरिक्ष क्षमताओं में वृद्धि हुई है और यह अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ सहयोग और साझा मिशनों की संभावना भी बढ़ाता है। उन्होंने बताया कि सक्रिय मलबा हटाने के लिए विकसित रोबोटिक आर्म और मैनिपुलेटर का उपयोग भविष्य में टूटे हुए उपग्रहों और अवशेषों को सुरक्षित तरीके से हटाने में किया जा सकेगा। इससे न केवल अंतरिक्ष में सुरक्षित संच. ालन सुनिश्चित होगा, बल्कि नए उपग्रहों और मिशनों के लिए सुरक्षित कक्षा भी उपलब्ध होगी।

मंत्री ने बताया कि इसरो लगातार अंतरिक्ष मलबे पर निगरानी रख रहा है और ट्रैकिंग सिस्टम के माध्यम से किसी भी खतरे का समय रहते पता लगाया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि भारत की यह पहल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अंतरिक्ष मलबा वैश्विक समस्या बन चुका है और इसे नियंत्रित करना सभी देशों के लिए चुनौतीपूर्ण है। भारत की सक्रिय तकनीकी प्रगति और नीति निर्धारण इस दिशा में एक उदाहरण प्रस्तुत करता है।

गुरू नाभा दास जी के जन्मदिवस पर 7 अप्रैल को निकलेगी भव्य शोभायात्रा

सबका जम्मू कश्मीर

गुरदासपुर/पंजाब। गुरदासपुर में गुरु नाभा दास जी के जन्मदिवस के उपलक्ष्य में 7 अप्रैल को भव्य शोभायात्रा निकाली जाएगी। यह शोभायात्रा शिरोमणि मंदिर, गांव हल्ला से हर वर्ष की तरह इस बार भी श्रद्धा और सम्मान के साथ निकलेगी।

कार्यक्रम में धार्मिक, सामाजिक और राजनी. तिक क्षेत्रों से जुड़ी कई गणमान्य हस्तियों के शामिल होने की संभावना है। गुरु नाभा दास महासमिति के सदस्यों द्वारा शोभायात्रा में आने वाले सभी श्रद्धालुओं का दिल से स्वागत और सम्मान किया जाएगा।

शोभायात्रा से पहले सुबह मंदिर में पूजा–अर्चना की जाएगी तथा गुरु जी को लंगर का भोग लगाया जाएगा। इसके बाद प्रसाद और लंगर सुबह 9 बजे से पूरे दिन चलता रहेगा, जिसकी सेवा मंदिर कमेटी गांव हल्ला के सेवेदारों द्वारा की जाएगी।

समस्त संगत से अपील की गई है कि वे 7 अप्रैल को सुबह 10 बजे शिरोमणि मंदिर, गांव हल्ला पहुंचकर शोभायात्रा में शामिल हों, पुण्य के भागीदार बनें और गुरु जी का आशीर्वाद प्राप्त करें।

माता बाला सुंदरी मंदिर में देवी भागवत कथा, भक्तिमय माहौल से गूंजा क्षेत्र

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, माता बाला सुंदरी मंदिर में इन दिनों धार्मिक माहौल बना हुआ है। यहाँ संत सुभाष शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाई जा रही है।

कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। वे माता रानी का आशीर्वाद लेने के साथ कथा सुनकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संत सुभाष शास्त्री अपने प्रवचनों में भक्ति, धर्म और जीवन के आदर्शों के बारे में सरल भाषा में समझा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु भाव–विभोर हो रहे हैं। मंदिर परिसर में भजन–कीर्तन और कथा का आयोजन लगातार जारी है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

माता बाला सुंदरी मंदिर में देवी भागवत कथा, भक्तिमय माहौल से गूंजा

सबका जम्मू कश्मीर

कठुआ, माता बाला सुंदरी मंदिर में इन दिनों धार्मिक माहौल बना हुआ है। यहाँ संत सुभाष शास्त्री द्वारा श्रद्धालुओं को श्रीमद् देवी भागवत कथा सुनाई जा रही है।

कथा के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंच रहे हैं। वे माता रानी का आशीर्वाद लेने के साथ कथा सुनकर आध्यात्मिक लाभ प्राप्त कर रहे हैं। संत सुभाष शास्त्री अपने प्रवचनों में भक्ति, धर्म और जीवन के आदर्शों के बारे में सरल भाषा में समझा रहे हैं, जिससे श्रद्धालु भाव–विभोर हो रहे हैं। मंदिर परिसर में भजन–कीर्तन और कथा का आयोजन लगातार जारी है, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय बना हुआ है।

कोटपुनु में 6वां वंश वॉलीबॉल टूर्नामेंट सम्पन्न, 25 टीमों ने लिया हिस्सा, महिलाओं ने भी दिखाया दम

सबका जम्मू कश्मीर

मढ़ीन, तहसील मढ़ीन के गांव कोटपुनु में आयोजित दो दिवसीय 6वें वंश वॉलीबॉल टूर्नामेंट में कुल 25 टीमों ने भाग लिया, जिनमें 3 महिला टीमें भी शामिल रहीं। टूर्नामेंट के दौरान खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया।

टूर्नामेंट का उद्घाटन पहले दिन कोटपुनु हाई सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा किया गया, जिन्हें मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। इस मौके पर उन्हें गुलदस्ता भेंट कर सम्मानित किया गया।

पहले दिन महिला टीमों के बीच मुकाबले खेले गए, जिसमें जम्मू के रामनगर से आई लड़कियों की टीम ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए फाइनल पर कब्जा जमाया। दूसरे दिन बाहरी राज्यों से आई टीमों के बीच भी कड़े मुकाबले देखने को मिले।

टूर्नामेंट के आयोजकों में पूर्व सरपंच विनय शर्मा और अन्य सदस्यों ने बताया कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के युवाओं को खेलों की ओर प्रेरित करना और नशे जैसी बुराइयों से दूर रखना है। उन्होंने कहा कि खेल ही युवाओं को सही दिशा दे सकते हैं।

विनय शर्मा ने विशेष रूप से महिला खिलाड़ियों की सराहना करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की बेटियों को भी खेलों में आगे आने का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों, खासकर बेटियों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें, ताकि वे भविष्य में देश और क्षेत्र का नाम रोशन कर सकें।

अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई में प्रवेश शुरू

सबका जम्मू कश्मीर

मुंबई : अथर्व विश्वविद्यालय मुंबई में शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह विश्वविद्यालय यूजीसी, भारत सरकार से मान्यता प्राप्त तथा महाराष्ट्र सरकार द्वारा अनुमोदित है। यहां इंजीनियरिंग (बी.टेक, एम.टेक, पीएच.डी.), प्रबंधन (बीबीए/एमबीए), होटल प्रबंधन, कंप्यूटर अनुप्रयोग (बीसीए/एमसीए) तथा डिजाइन, फैशन, फिल्म और टीवी जैसे विभिन्न पाठ्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

27 वर्षों की शैक्षणिक विरासत के साथ यह संस्थान मुंबई के मलाड मरवे रोड, मलाड पश्चिम में स्थित है। विश्वविद्यालय की स्थापना इसके संस्थापक और कुलाधिपति सुनील राणे के नेतृत्व में की गई है। संस्थान में परियोजना एवं शोध आधारित नवाचारी शिक्षा प्रणाली अपनाई जाती है, जिससे छात्रों को व्यावहारिक ज्ञान के साथ उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार किया जा सके।

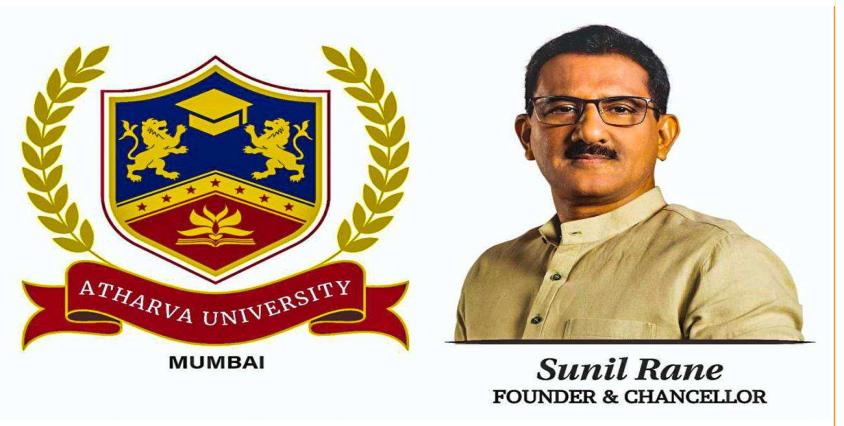

विश्वविद्यालय का 'प्रोजेक्ट फ्राइडे' पहल विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिसके माध्यम से विद्यार्थियों की रचनात्मकता और नवाचार क्षमता को विकसित करने पर जोर दिया जाता है। यहां आधुनिक प्रयोगशालाएं, उच्च स्तरीय अधोसंरचना, अनुभवी शिक्षकों का मार्गदर्शन और बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाता है।

छात्रों को प्रतिष्ठित कंपनियों में इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं। साथ ही, शहीदों की बेटियों, जम्मू–कश्मीर तथा पूर्वोत्तर राज्यों के विद्यार्थियों के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम में छात्रवृत्ति की सुविधा भी उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से या संपर्क नंबर पर जानकारी प्राप्त कर प्रवेश प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।

BEFORE THE LEARNED EXECUTIVE MAGISTRATE 1ST CLASS TEHSILDAR NAGRI PAROLE

Bansi Lal S/o Chhajju Ram R/o Pandori Tehsil Nagri Parole and Distt Kathua.

(Applicant)

V/S

Block Development Officer, Nagri parole

(Respondent)

In the matter of: Application for directing Block Development Office Nagri Parole to enter the Date of Birth in the Birth register.

Name of the Guardian: Bavita Devi D/o Hans Raj & Mother Name Bachni Devi.

Date of Birth: 11-08-1974.

Place of Birth: At HOME (Pandori).

R/Sir,

The applicant most humbly submits as under:-

That the applicant is permanent resident of Village Pandori Tehsil NAGRI PAROLE, District Kathua J&K UT. That the Date of Birth Bavita Devi is 11-08-1974. That unfortunately the Date of Birth of the child has not been entered in the register of Birth kept at Respondents Office Nagri Parole nor in the record of Chowkidar concerned. That the applicant is in dire need of Date of Birth of the child from the register of Birth kept at Respondents Office Nagri Parole. An affidavit in sport of the application is attached here with. It is therefore humbly prayed that the Block Development Office Nagri parole may kindly be directed to enter the Date of Birth of the child in the register of Birth kept at Respondents.

साप्ताहिक
सबका जम्मू कश्मीर

एलजी मनोज सिन्हा श्री रघुनाथ जी की जम्मू आरती में शामिल हुए

सबका जम्मू कश्मीर

जम्मू : उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज जम्मू संभाग के नदी तटवर्ती कस्बों और गांवों में स्थानीय समुदायों के सहयोग से दैनिक या साप्ताहिक संध्या आरती आयोजित करने का आह्वान किया। उपराज्यपाल ने कहा, "मैं लोगों से आग्रह करता हूं कि वे जम्मू संभाग के नदी तटवर्ती कस्बों और गांवों में दैनिक या साप्ताहिक संध्या आरती आयोजित करें। आरती के दीयों से प्रज्वलित प्रकाश समाज को हमारी समृद्ध संस्कृति के प्रति जागृत करेगा और युवा पीढ़ी को हमारे पवित्र ग्रंथों के शाश्वत श्लोकों से जोड़ेगा।" उपराज्यपाल ने श्री रघुनाथ जी की जम्मू आरती संस्था द्वारा आयोजित श्री रघुनाथ जी की जम्मू आरती में भाग लिया। उन्होंने आयोजकों के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि आज समर्पित पुरुषों और महिलाओं द्वारा की गई यह अनूठी जम्मू आरती, नारी शक्ति और अर्धनारीश्वर के प्रति भारत की शाश्वत श्रद्धा को दर्शाती है, साथ ही प्रत्येक जीवित प्राणी पर दिव्य आशीर्वाद का आह्वान करती है। उपराज्यपाल ने कहा, "मेरा दृढ़ विश्वास है कि संध्या आरती आत्मा का अनुशासन है। यह समाज को हमारे अस्तित्व के स्रोत को देखने और कृतज्ञ होने के लिए प्रेरित करने का एक सचेत और जागृत प्रयास है।" उपराज्यपाल ने यह भी कहा कि आरती में उठने वाली हर लौ पूर्ण भक्ति का अर्पण है, हर प्रार्थना अनंत से संवाद है और बिताया गया हर पल आंतरिक यात्रा की ओर एक कदम है।

"इस तेजी से बदलती दुनिया में, जीवन की निरंतर गति के बीच, हमें अपने भीतर विद्यमान सबसे बड़े खजाने को याद दिलाने के लिए एक ध्यानपूर्ण क्षण की आवश्यकता है। मेरा मानना छहै कि जम्मू आरती समाज के हर वर्ग को इस अनमोल आंतरिक संपदा को पुनः खोजने का अवसर प्रदान करती है," उपराज्यपाल ने कहा। उपराज्यपाल ने कहा कि मंदिरों के शहर के रूप में प्रसिद्ध सुंदर शहर जम्मू को आध्यात्मिकता के वैश्विक केंद्र और आध्यात्मिक पर्यटन के मानचित्र पर एक प्रमुख गंतव्य के रूप में प्रस्तुत करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

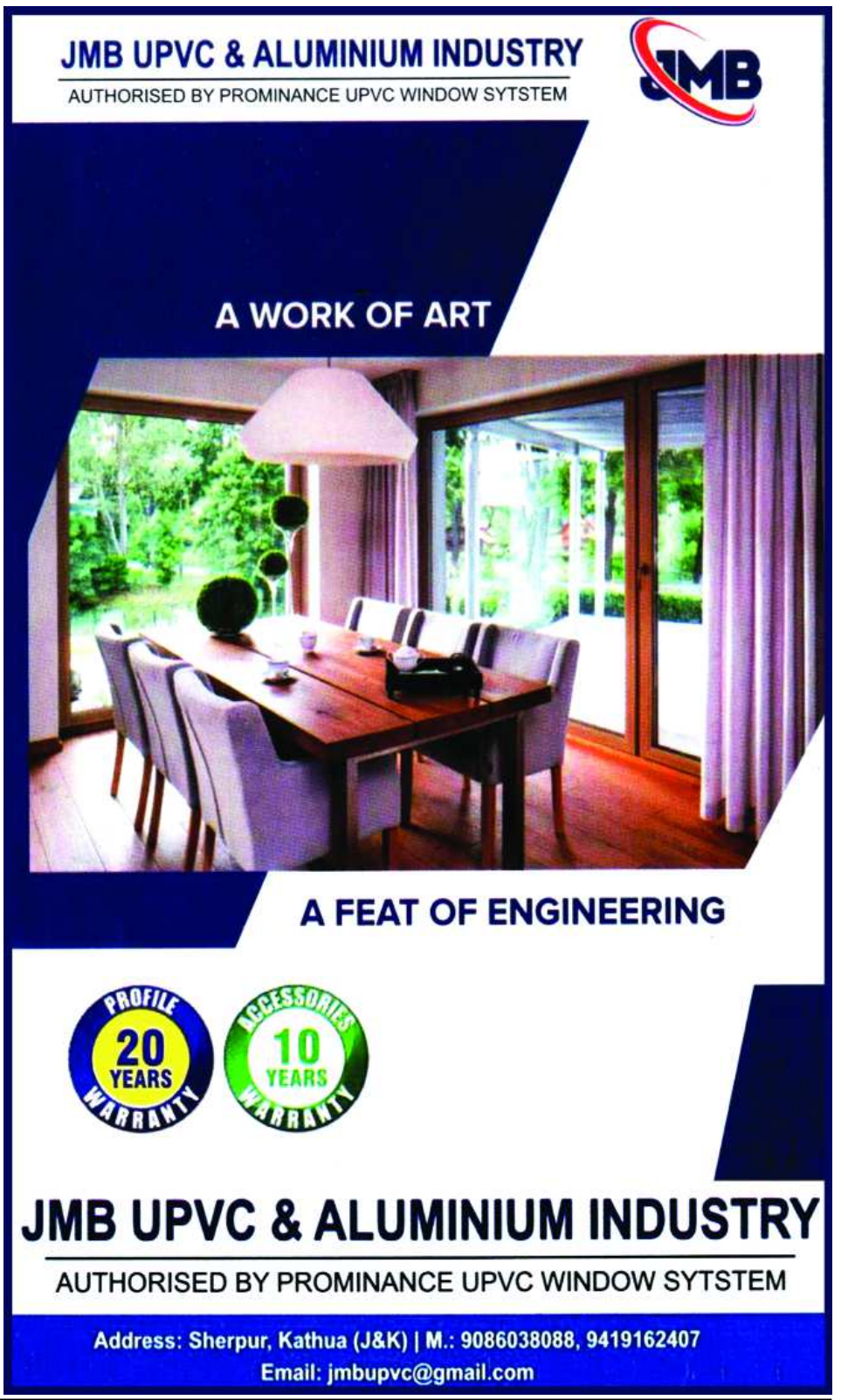

स्वामित्व, मुद्रक, प्रकाशकः राज कुमार द्वारा एम/एस डी. आर प्रिंटिंग प्रेस, बैन बजाल्ता, तहसील जम्मू से मुद्रित एवं नगरी पैरोल नगरी, जिला कठुआ, जम्मू और कश्मीर पिन.कोड नंः 184151 । संपादकः राज कुमार